लखनऊ

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

शनिवार, 19 सितंबर, 203

वर्ष : 12 । अंकः 26

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

प्रेम जीवन है, तो नफरत मृत्यु के समान है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथ में है।

TODAY WEATHER

DAY	NIGHT
32°	28°
Hi	Low

संक्षेप

दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने बाइक को कई मीटर तक घसीटा, 73 साल के बुजुर्ग की ऐसी हरकत!

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के आरके पुरम इलाके में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। आरके पुरम मेट्रो स्टेशन के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बाइक को काफी दूर तक घसीटते हुए ले गई। गनीमत यह रही कि बाइक पर बैठा युवक समय रहते नीचे छिटक गया, जिससे उसकी जान बाल-बाल बच गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद भीड़ ने आरोपी चालक को दबोच लिया, जिसकी पहचान 73 वर्षीय बुजुर्ग के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, यह घटना 17 सितंबर की रात करीब 10 बजे अफ्रीका एवेन्यू रोड पर घटी। मुनिरका गांव का रहने वाला 21 वर्षीय तनीष टोकस सड़क किनारे अपनी काली बाइक पर बैठा हुआ था। इसी दौरान वसंत कुंज निवासी 73 वर्षीय वेणु गोपाल अपनी नीली कार लेकर पहुंचे और सीधी टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही तनीष सड़क पर जा गिरे, जबकि कार बाइक को कई मीटर तक सड़क पर घसीटती चली गई। पुलिस ने बताया कि पीड़ित युवक कार के साथ नहीं घसीटा और प्राथमिक चिकित्सा जांच में उसे कोई गंभीर चोट नहीं पाई गई है। हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों ने तुरंत घेराबंदी कर कार चालक को रोक लिया। सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में भीड़ कार चालक को बाहर निकालती दिख रही है, जहां गुस्से में तमतमाई एक महिला आरोपी बुजुर्ग को थप्पड़ मारती नजर आ रही है। वहीं, आरोपी बुजुर्ग दोनों हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगता दिख रहा है।

ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में 35 मिनट की देरी, एयर इंडिया एक्सप्रेस के 8 क्रू सदस्य निलंबित

नई दिल्ली। दुबई से अमृतसर आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट के आठ क्रू सदस्यों को पोस्ट-फ्लाइट अनिवार्य प्रक्रिया में देरी भारी पड़ गई। 2 अगस्त 2026 को दुबई से अमृतसर पहुंची फ्लाइट के क्रू को लैंडिंग के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर पोस्ट-फ्लाइट डिक्लेरेशन जमा करना था, लेकिन इसमें 35 मिनट की देरी हो गई। विमानन नियमों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लैंड करने के दो घंटे के भीतर क्रू सदस्यों को पोस्ट-फ्लाइट डिक्लेरेशन और अनिवार्य ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। हालांकि, संबंधित फ्लाइट के क्रू ने डिक्लेरेशन 2 घंटे 35 मिनट बाद जमा किया। प्रक्रियात्मक देरी सामने आने के बाद एयरलाइन के अनिवार्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत सभी क्रू सदस्यों का साइकोएक्टिव पदार्थों के सेवन की जांच के लिए मेडिकल टेस्ट कराया गया। राहत की बात यह रही कि सभी आठ सदस्यों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। हालांकि, टेस्ट रिपोर्ट में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं मिलने के बावजूद एयरलाइन प्रबंधन ने निर्धारित समय सीमा के उल्लंघन को गंभीरता से लिया। सूत्रों के मुताबिक, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने घटना की विस्तृत रिपोर्ट नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को सौंप दी है।

राहुल के पार्टी तोड़ने के आरोपों पर भाजपा का पलटवार

रिजिजू ने कांग्रेस को कहा भस्मासुर, याद दिलाया इतिहास

नई दिल्ली, एजेंसी। राजनीतिक दलों को तोड़ने के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। मामले को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और वरिष्ठ भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को अपने पुराने फैसलों और इतिहास को देखने की नसीहत दी है।

दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस जो बातें अपने लिए कहनी चाहिए, वे भाजपा पर मढ़ रहे हैं। रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी की तुलना 'भस्मासुर' से की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसा भस्मासुर है, जो अपने संपर्क में आने वाली हर राजनीतिक पार्टी को भस्म कर देती है।

रिजिजू ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और एनसीपी जैसी पार्टियां कांग्रेस से ही निकली हैं। खुद कांग्रेस भी किसी अन्य दल से टूटकर बनी थी। उन्होंने कहा कि पार्टियों को तोड़ने और नुकसान पहुंचाने का काम हमेशा कांग्रेस ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है। यह सफलता किसी पार्टी को तोड़कर हासिल नहीं की गई है। भाजपा कांग्रेस की तरह गंदा खेल नहीं खेलती।

रिजिजू ने कांग्रेस को याद दिलाया इतिहास

केंद्रीय मंत्री ने 1989 के राजनीतिक घटनाक्रम को भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि वी. पी. सिंह कांग्रेस से बाहर निकलकर प्रधानमंत्री बने थे। तब कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर को समर्थन देने का दिखावा करके साजिश रची और वी. पी. सिंह की सरकार गिरा दी। फिर कुछ ही महीनों में चंद्रशेखर से भी समर्थन वापस लेकर उनकी सरकार को गिरा दिया।

'अपनी पार्टी का इतिहास भी नहीं जानते'

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी जिन पार्टियों का नाम लेकर भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें उनके इतिहास की भी जानकारी नहीं है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, राहुल गांधी के बारे में देश में यह धारणा है कि उन्हें न देश के बारे में कुछ पता है। न समाज के बारे में कुछ पता है। न देश की संस्कृति के बारे में कुछ पता है और न ही देश के धर्म के बारे में कुछ पता है। लेकिन आज उन्होंने एक अद्भुत ट्वीट किया है। उससे लगता है कि उन्हें अपनी पार्टी के बारे में भी कुछ नहीं पता।

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते समय यह भी नहीं देखते कि जिन पार्टियों का वह नाम ले रहे हैं, वे कौन हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने एनसीपी, शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस का नाम लेकर आरोप लगाया है कि भाजपा इन तीनों पार्टियों को खत्म कर रही है। कांग्रेसियों के लिए आदरणीय और देश के लिए निंदनीय राहुल गांधी जी, आप इतना भी नहीं पढ़ पाते कि एनसीपी का फुल फॉर्म नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है। ये कांग्रेस से टूटी हुई है। भाजपा ने कहा कि शरद पवार विदेशी मूल के नेतृत्व के मुद्दे पर 1999 में कांग्रेस से अलग हुए थे।

भाजपा प्रवक्ता ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वह अपनी ही पार्टी के इतिहास को नहीं जानते। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस का भी जिक्र किया। पार्टी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नाम में ही कांग्रेस शब्द है। उन्होंने कहा, 1997 में ममता बनर्जी कांग्रेस के अंदर की परिस्थितियों के कारण अलग हुई थीं। इसके बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई। भाजपा ने कहा कि इसके बाद ममता बनर्जी ने 'तृण' और 'मूल' से कांग्रेस को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को ये भी नहीं पता है कि उनके परिवार ने क्या-क्या कमाल किए हैं।

कई राज्यों में विलेन बना मौसम, सैकड़ों सड़कें प्रभावित

चंडीगढ़, एजेंसी। देश के कई राज्यों में मौसम आफत बन चुका है। इस आफत ने कई सड़कों को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। हिमाचल-उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में तो बर्फबारी ने जनजीवन अस्तव्यस्त कर दिया है। हिमाचल के गुरुवार सुबह रोहतांग, भरमौर और मनाली के पहाड़ों पर एक से डेढ़ ईंच बर्फ गिरी। जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी के काबुल गली में बर्फबारी हुई है। उत्तराखंड के केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और चमोली स्थित रुद्रनाथ जी में भी ओलों के साथ हल्की बर्फ गिरी है। वहीं, पिछले दिनों भारी बारिश से क्षतिग्रस्त अर्धकुंवारी-हिमकोटी मार्ग आखिरकार दुरुस्त कर लिया गया है।

बुधवार सुबह करीब सात बजे इस मार्ग को श्रद्धालुओं की पैदल आवाजाही के लिए फिर से खोल दिया गया।

'वोट चोरी, सरकार चोरी और अब पार्टी चोरी'

टीएमसी का नाम और सिंबल फ्रीज करने पर राहुल का EC पर हमला

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने चुनाव आयोग के उस फैसले पर सवाल खड़े किए, जिसमें आयोग ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनावों में तृणमूल कांग्रेस को पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न (सिंबल) इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज शुक्रवार सुबह चुनाव आयोग (EC) को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर मिलकर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'पहले शिवसेना, फिर NCP और अब तृणमूल कांग्रेस। हर बार एक ही पैटर्न - BJP और चुनाव आयोग मिलकर एक पार्टी को तोड़ते हैं। फिर उसका चुनाव चिह्न छीन लिया जाता है।' कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए लिखा, 'जब पूरी की पूरी पार्टी चोरी हो सकती है, तो करोड़ों भारतीयों के वोट चोरी होना भी हैरानी की बात नहीं।' राहुल गांधी ने लोकतंत्र पर हमले की बात करते हुए आगे लिखा, 'वोट चोरी। सरकार चोरी। अब पार्टी चोरी। ये हमारे लोकतांत्रिक पतन के प्रतीक बन गए हैं। ECI की संवैधानिक जिम्मेदारी जनादेश की रक्षा करना है, मगर उल्टा वो उन ताकतों की मदद कर रहा है, जो जनता के फैसले को ही पलट देते हैं।' कांग्रेस नेता ने ममता बनर्जी के समर्थन में अपनी बात रखते हुए लिखा, 'यह लड़ाई सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं है। यह हर राजनीतिक दल, हर मतदाता की लड़ाई है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहता है।'

ममता गुट को 'फुटबॉल', अरूप रॉय गुट को 'लिफाफा' सिंबल

कोलकाता, एजेंसी। चुनाव आयोग ने मूल तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके चुनाव चिह्न पर रोक लगाने के बाद, अब दोनों गुटों को नई आधिकारिक पहचान सौंप दी है।

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम आवंटित किया गया है और आगामी चुनावी मैदान में वे 'फुटबॉल खिलाड़ी' के चुनाव चिह्न के साथ उतरेंगे।

चुनाव आयोग के आदेश के बाद दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को 18 सितंबर की सुबह तक अपने-अपने लिए तीन नए नाम और चुनाव चिह्न के विकल्प सौंपने का निर्देश दिया गया था। ममता बनर्जी ने इस फैसले पर अपनी कड़ी आपत्ति जताते हुए गुरुवार रात को अपने विकल्प आयोग को सौंपे थे। पीटीआई के अनुसार, चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट के नए नाम पर अपनी मुहर लगा दी है। ममता गुट को अब आधिकारिक तौर पर 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' का नाम दिया गया है। ममता बनर्जी की पार्टी अब फुटबॉल खिलाड़ी के चुनाव चिह्न पर मैदान में उतरेगी। वहीं दूसरी तरफ, अरूप रॉय के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी गुट को भी चुनाव आयोग द्वारा एक नई राजनीतिक पहचान दी गई है। इस गुट को आधिकारिक तौर पर 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम दिया गया है और इन्हें चुनाव चिह्न के रूप में 'लिफाफा' आवंटित किया गया है। इन नए नामों और चुनाव चिह्नों के आधिकारिक रूप से लागू होने के साथ ही, दोनों गुटों ने एक बड़ी प्रशासनिक बाधा पार कर ली है। अब वे आगामी उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं, जबकि असली पार्टी की विरासत को लेकर अंतिम विवाद अभी भी जारी है। चुनाव आयोग का मकसद आगामी नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनावों से पहले दोनों गुटों को समान स्थिति में रखना था, जिसके चलते दोनों पक्षों को मूल नाम और सिंबल के इस्तेमाल से रोक दिया गया था।

हाईवे पर छोड़े आवारा पशु तो नपेंगे मालिक, सरकार ने जारी किया सख्त फरमान

नई दिल्ली, एजेंसी। देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों और तेज रफ्तार एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने वाले वाहन चालकों को अब अचानक सामने आने वाले आवारा पशुओं के खतरे से मुक्ति मिलने जा रही है। हाईवे पर बेसहारा मवेशियों के कारण आए दिन होने वाले जानलेवा सड़क हादसों पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में एक विस्तृत 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' जारी किया है। नए नियमों के तहत यदि किसी ने अपने पशुओं को हाईवे या एक्सप्रेसवे पर लावारिस छोड़ा, तो मालिक की पहचान कर उस पर भारी-भरकम जुर्माना ठोका जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय का यह सख्त कदम सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद सामने आया है, जिसमें हाईवे से आवारा पशुओं को हटाने के लिए एक ठोस और स्थायी तंत्र विकसित करने का आदेश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने सड़कों पर पशुओं की वजह से होने वाली भीषण दुर्घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया था। अदालत के कड़े रुख के बाद केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से यह एसओपी जारी की है, जिसका प्राथमिक मकसद तेज रफ्तार वाली सड़कों को पूरी तरह सुरक्षित और दुर्घटनामुक्त बनाना है। नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण , एनएचआईडीसीएल और राज्यों के लोक निर्माण विभाग में नोडल एजेंसियां गठित की जाएंगी।

आईफोन की भीड़ देख सोनू सूद ने कसा तंज, कहा-

असली अपग्रेड फोन का नहीं समाज का करो

मुंबई, एजेंसी। भारत में दिखावे के चक्कर ज्यादा खर्च करने का चलन नया नहीं है। शुक्रवार को भी एक नजारा दिखा, जब आईफोन 18 प्रो सीरीज के फोन खरीदने के लिए सुबह से ही एप्पल स्टोर के बाहर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इसे देखते हुए अभिनेता सोनू सूद ने लोगों को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि महंगे फोन से झूठी शान दिखाने और कर्जदार बनने से बेहतर है कि लोग अपनी गाढ़ी कमाई और ऊर्जा को समाज की भलाई में लगाएं। अभिनेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें एप्पल स्टोर के बाहर ग्राहकों की भारी भीड़ दिख रही है। अभिनेता ने अपनी इस पोस्ट के जरिए लोगों को केवल स्मार्टफोन के दिखावे और कर्ज के जाल में फंसने के बजाय सामाजिक सुधार और दूसरों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करने की सीख दी है। उन्होंने लिखा, नया फोन, नई ईएमआई, वही पुराने बिल! शायद यह समय सिर्फ अपने फोन को अपग्रेड करने का नहीं, बल्कि समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कतार (लाइनों) में खड़े होने का है। असली अपग्रेड एक बेहतर समाज का निर्माण है।

बता दें कि एप्पल के नए आईफोन 18 प्रो सीरीज की बिक्री शुक्रवार सुबह 8 बजे से भारत में शुरू हो गई है। दिल्ली, नोएडा, मुंबई, बेंगलुरु और अन्य बड़े शहरों में एप्पल स्टोर और आधिकारिक दुकानों के बाहर लोग सुबह से लंबी कतारों में खड़े नजर आए। भारत में इसके बेस मॉडल की कीमत 1,64,900 रुपए से शुरू है। आईफोन 18 प्रो को लेकर पूरे देश में खुमार इस कदर है कि कई लोगों ने पहले से ही ऑनलाइन प्री-बुकिंग करा रखी थी।

मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की आहट, मंत्रियों का 'रिपोर्ट कार्ड' परखेंगे पीएम, 23-24 सितंबर को महामंथन

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र की सत्ता में अपने तीसरे कार्यकाल के अहम पड़ाव पर खड़ी मोदी सरकार में क्या जल्द ही बड़ा फेरबदल होने जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगले सप्ताह बुलाई गई दो दिवसीय विशेष 'चिंतन बैठक' ने राजनीतिक गलियारों और लुटियंस दिल्ली में हलचल तेज कर दी है। 23 और 24 सितंबर को होने वाली इस हाई-प्रोफाइल बैठक में सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों को दिल्ली में ही मौजूद रहने का फरमान जारी किया गया है। आधिकारिक तौर पर इसे नीतियों और प्रशासनिक सुधारों की समीक्षा बताया जा रहा है, लेकिन बैठक के समय को देखते हुए मंत्रिपरिषद में व्यापक फेरबदल की अटकलें चरम पर हैं। यह बैठक नियमित कैबिनेट बैठकों की तरह केवल फैसलों पर मुहर लगाने वाली नहीं होगी, बल्कि एक गहन मंथन सत्र के रूप में आयोजित की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रियों को अलग-अलग समूहों में बांटा जाएगा, जहां वे शासन व्यवस्था, संवाद, सुधार और जनहित के मुद्दों पर सीधे विचार-विमर्श करेंगे। कई प्रमुख मंत्रालयों को अपनी उपलब्धियों और सुधारों पर विशेष प्रेजेंटेशन देने के निर्देश भी दिए गए हैं। पीएम मोदी स्वयं यह परखेंगे कि फाइलों में बनी नीतियां धरातल पर आम जनता के 'ईज ऑफ लिविंग' में कितना बदलाव ला पा रही हैं। राजनीतिक हलकों में इस चिंतन बैठक को संभावित कैबिनेट फेरबदल की पृष्ठभूमि के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार अपने वर्तमान कार्यकाल के रणनीतिक मोड़ पर है और आने वाले महीनों की राजनीतिक व नीतिगत चुनौतियों से निपटने के लिए नई ऊर्जा की जरूरत महसूस की जा रही है।

पश्चिम बंगाल एसआईआर : 38 लाख अपीलों में अबतक सिर्फ 1 लाख का निपटारा, चुनाव आयोग ने SC को दी जानकारी

58 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम बाहर होने का दावा

हलफनामा दायर करने वाले प्रसेनजीत बोस ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के गणना चरण के दौरान 58 लाख से अधिक मतदाताओं को बाहर कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियों के चरण में नाम शामिल करने के लिए 9.64 लाख आवेदन और नाम हटाने के लिए 99,000 से अधिक आवेदन मिले थे। इसके बावजूद, 28 फरवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में केवल 1.82 लाख नए नाम ही जोड़े गए। आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 17 दिसंबर 2025 ड्राफ्ट से 7 अगस्त 2026 के बीच फॉर्म 6 के तहत 34.13 लाख नए आवेदन प्राप्त हुए थे।

नई दिल्ली, एजेंसी। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत मतदाता सूची से नाम हटाने या जोड़ने के खिलाफ दायर 37 लाख से अधिक अपीलें अभी भी लंबित हैं।

शीर्ष अदालत में दायर अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि अदालत द्वारा नियुक्त ट्रिब्यूनल्स ने अब तक दायर 38.20 लाख अपीलों में से केवल लगभग 1.02 लाख का ही निपटारा किया है।

यह जवाब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष दाखिल किया गया। पीठ ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग से जवाब मांगा था, जिसमें एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हटाए गए मतदाताओं के दावों और आपत्तियों का विधानसभा क्षेत्रवार डेटा सार्वजनिक करने की मांग की गई थी।

चुनाव आयोग ने बताया कि मतदाता सूची के एसआईआर से संबंधित आदेशों के खिलाफ कुल 38,20,683 अपीलें दायर की गई थीं। इनमें से केवल 1,02,231 अपीलों का ही निपटारा हो सका है, जबकि 37,18,452 अपीलें अभी भी लंबित हैं। हालांकि, आयोग के हलफनामे में यह अलग-अलग विवरण नहीं दिया गया कि इनमें से कितनी अपीलें नाम हटाए जाने के खिलाफ थीं और कितनी अपीलें सूची में नए नाम शामिल किए जाने के विरोध में दर्ज की गई थीं।

राघव चड्ढा ने आप को एक्स गर्लफ्रेंड बताकर किया कटाक्ष, कहा- कहीं अपने हाथ की नस न कांट लें

गुरदासपुर , एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि उनका हाल एक्स-गर्लफ्रेंड जैसा है। मुझे उनकी चिंता होती है कि कहीं किसी दिन मेरी याद में अपने हाथ की नसे न कांट लें। भाजपा सांसद राघव चड्ढा ने पंजाब के गुरदासपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, उनका (आम आदमी पार्टी) हाल उस एक्स-गर्लफ्रेंड जैसी है, जिसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर आगे निकल गया और जिंदगी में आगे निकल गया है, लेकिन अब भी वो मेरे इश्क और प्यार में पागल हैं। मुझे उनकी चिंता होती है कि कहीं किसी दिन मेरी याद में अपने हाथ की नसे न कांट लें। राघव चड्ढा शुक्रवार को गुरदासपुर में भाजपा की नशे के खिलाफ शुरू हो रही यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे। बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा राज्य में शुरू से चार यात्राएं शुरू कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इन यात्राओं का आगाज करेंगे।

पंजाब भाजपा के उपाध्यक्ष रविकरण सिंह काहलों ने कहा कि पंजाब, पंजाब के युवा और यहां की जमीन को बचाने के लिए भाजपा प्रदेश में यात्रा निकालने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह यात्रा 10 जिलों को कवर करेगी और 35 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी।

उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान नशे के शिकार हुए युवाओं और परिवारों के मुलाकात की जाएगी। हमारा संकल्प और उद्देश्य पंजाब की धरती से नशे को खत्म करना है। इसलिए इस यात्रा का नाम नशा मुक्त पंजाब यात्रा रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब से नशे, गैंगस्टर और भ्रष्टाचार को खत्म करके एक अच्छी सरकार देनी है। यहां डबल इंजन की सरकार बनानी है।

युवती के करीब पहुंची ब्लैक थार, फिर... नोएडा में खतरनाक ड्राइविंग का वीडियो

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। नोएडा में खतरनाक तरीके से थार चलाने का एक और मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर ब्लैक थार के दो वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में थार सवार युवक सड़क पर मौजूद लोगों को परेशान करता और उनके पास तेजी से गाड़ी ले जाता दिखाई दे रहा है। एक वीडियो में सड़क से गुजर रही युवती के पास भी थार ले जाकर उसे डराने की कोशिश की गई। वीडियो सामने आने के बाद नोएडा पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है।

हालांकि, पुलिस जांच में अभी यह साफ नहीं हुआ है कि वीडियो कब के हैं और इनमें दिखाई दे रहे वाहन और चालक की पहचान क्या है? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को नोएडा के सेक्टर-125 स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी के आसपास का बताया जा रहा है।

2 वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप

सोशल मीडिया पर वायरल दोनों वीडियो में ब्लैक थार नजर आ रही है। वीडियो में सड़क पर मौजूद लोगों के आसपास वाहन को तेज गति से चलाते हुए देखा जा सकता है। आरोप है कि चालक लोगों को डराने के लिए उनके बेहद करीब से गाड़ी निकाल रहा था। एक वीडियो में सड़क पर चल रही एक युवती के पास थार पहुंचती दिखाई देती है।

इसके बाद वाहन को लेकर युवती को परेशान करने और उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश किए जाने का दावा किया जा रहा है। दूसरे वीडियो में भी सड़क पर मौजूद लोगों के पास थार को ले जाते हुए देखा जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने नोएडा पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की है।

वीडियो की तारीख और जगह की हो रही जांच

पुलिस अब वायरल वीडियो की सच्चाई की जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वीडियो वास्तव में नोएडा का है या नहीं। इसके साथ ही वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया था और उसमें दिखाई दे रही थार किसकी है, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सोशल मीडिया पर कई बार पुराने वीडियो भी दोबारा वायरल हो जाते हैं। इसलिए इस मामले में यह भी जांच की जा रही है कि वायरल वीडियो किसी पुरानी घटना से जुड़े हैं या हाल की घटना के हैं।

पहले भी सामने आ चुके हैं थार के स्टंट के वीडियो

नोएडा में थार और दूसरे महंगे वाहनों से स्टंट और खतरनाक ड्राइविंग के वीडियो पहले भी सामने आते रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कई मामलों में वाहनों की पहचान कर कार्रवाई की है। कुछ वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई भी की गई है। पुलिस का कहना है कि सड़क पर इस तरह से वाहन चलाना दूसरे लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। ऐसे मामलों में यातायात नियमों के उल्लंघन के साथ-साथ अन्य धाराओं में भी कार्रवाई की जा सकती है, अगर जांच में संबंधित अपराध सामने आता है।

पुलिस बोली- जांच के बाद होगी कार्रवाई

नोएडा के एसीपी प्रवीण सिंह के मुताबिक, सोशल मीडिया पर सामने आए दोनों वीडियो को जांच में शामिल किया जाएगा। पुलिस वीडियो की तारीख, स्थान और वाहन की पहचान की जानकारी जुटा रही है। एसीपी के अनुसार, अगर जांच में वायरल वीडियो में यातायात नियमों का उल्लंघन या लोगों की जान को खतरे में डालने की बात सामने आती है, तो संबंधित वाहन और चालक की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

ऐतिहासिक भादो छठ मेला की तैयारियां तेज

जौनपुर। सरायख्वाजा क्षेत्र के में हर वर्ष आयोजित होने वाला ऐतिहासिक भादो छठ मेला इस बार 20 सितंबर, रविवार को लगेगा। मेले को लेकर दूर-दराज से दुकान लगाने वाले दुकानदारों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मेला स्थल पर झूले, खिलौने और लकड़ी से बने घर-गृहस्थी के सामान की दुकानें सजने लगी हैं। मेले को लेकर प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार, सरायख्वाजा गांव के प्राचीन सूरज कुंड तालाब के समीप लगने वाले इस मेले में श्रद्धालु तालाब में स्नान-ध्यान करने के बाद पास स्थित मंदिर में दर्शन-पूजन करते हैं। लोगों की मान्यता है कि ऐसा करने से चर्म रोग समेत विभिन्न बीमारियों से राहत मिलती है। इसी आस्था के चलते हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। भादो छठ मेले को किसान मेला भी कहा जाता है। यहां किसानों की जरूरत की सामग्री से लेकर बच्चों के खिलौने और घरेलू उपयोग की वस्तुएं तक उपलब्ध रहती हैं।

पर्यावरण को जाने के तहत क्विज प्रतियोगिता

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के भूगोल विभाग द्वारा विद्यार्थियों में पर्यावरणीय जागरूकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विषयगत ज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ' अपने पर्यावरण को जाने' क्विज प्रतियोगिता एवं संगोष्ठी का सफल आयोजन किया गया। अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. राम आसरे सिंह ने की। मुख्य वक्ता प्रो. शम्भू राम चैहान प्राचार्य द्वारा ओजोन दिवस के अवसर पर विषय केंद्रित बहुआयामी व्याख्यान प्रस्तुत किया गया । क्विज प्रतियोगिता का संचालन एवं कार्यवाही डॉ. विजय लक्ष्मी द्वारा कराई गई । कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. राम आसरे सिंह ने पर्यावरण संरक्षण एवं ओजोन परत की सुरक्षा के प्रति जागरूकता को समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता बताया। उन्होंने पर्यावरण बचाओ भविष्य बचाओ का नारा दिया । कार्यक्रम ने विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चुनौतियों को समझने तथा प्रकृति के प्रति जिम्मेदार एवं संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रेरित किया गय मुख्य अथिति ने बच्चों को ओजोन के निर्माण, उसकी महत्ता और ओजोन के नष्ट होने पर होने वाले प्रभावों का उल्लेख किया । बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं की रोकथाम की जिम्मेदारी स्वयं लेने के लिए प्रोत्साहित किया । महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्साह पूर्वक बढ़-चढ़कर सहभागिता के साथ प्रतिभाग किए प्रतियोगिता में पर्यावरण, ओजोन परत, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधन, प्रदूषण, सतत विकास तथा भूगोल से संबंधित प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों के ज्ञान एवं त्वरित निर्णय क्षमता का परीक्षण किया गया।प्रतियोगिता में लिखित प्रश्नोत्तरी तथा पीपीटी आधारित रैपिड फायर क्विज में कई चरणों के साथ साथ व्याख्यान आयोजित किया गया। लिखित चरण के प्रदर्शन के आधार पर चयनित विद्यार्थियों को यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं गोमती नामक चार टीमों में विभाजित कर अंतिम चरण में प्रतिभाग कराया गया। इस तरह विभिन्न टीम प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया ।विद्यार्थियों ने टीम भावना, विषयगत दक्षता एवं उत्साह का प्रभावी प्रदर्शन किया।

ब्लॉक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण समापन

जौनपुर। ब्लाक संसाधन केन्द्र करंजाकला पर निपुण भारत मिशन के तहत 1 अगस्त से आयोजित पाच दिवसीय बुनियादी भाषा एवं संख्या ज्ञान तथा एन.सी.ई.आर.टी .की पाठ्यपुस्तकों पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण का 18सितम्बर को समापन हुआ। प्रशिक्षण के दौरान गतिविधि आधारित बाल केन्द्रित अधिगम, अनुभवात्मक शिक्षण, सतत - मूल्यांकन, कक्षा शिक्षण में नवीन शिक्षक संदर्शिका की प्रभावी उपयोगिता के साथ- साथ. कक्षा वार विभाग द्वारा प्राप्त एन.सी.ई.आर.टी .की नवीन पाठ्य पुस्तकों में किए गए परिवर्तन प्रिंट रिच मटेरियल, शैक्षिक कैलेंडर, स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम, समग्र प्रगति पत्र ,प्रथम संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गए सैम्पल पेपर के आधार पर भाषा व गणित में बेस लाइन, मिड लाइन व इंडलाइन आकलन प्रपत्र भरने के साथ-साथ निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के अनुपालन आदि के संदर्भ में विस्तारपूर्वक जानकारी साझा की गई ।

होमगार्ड भर्ती की दौड़ में अभ्यर्थी की मौत : अचानक बेहोश होकर गिरा शिवम, बीटेक की पूरी की थी पढ़ाई

आर्यावर्त संवाददाता

मुरादाबाद। मुरादाबाद में 9वीं वाहिनी पीएसी मैदान में चल रही होमगार्ड भर्ती की दौड़ के दौरान शुक्रवार सुबह एक अभ्यर्थी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। अभ्यर्थी को आनन-फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

उसकी पहचान शिवम यादव पुत्र विनोद यादव निवासी राजपुर कला, मणिनाथ कॉलोनी बरेली निवासी के तौर पर हुई। अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब आठ बजे दौड़ के दौरान शिवम अचानक बेहोश होकर गिर पड़े।

भर्ती प्रक्रिया में मौजूद लोगों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया ।शिवम के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। उनके परिवार में पत्नी कोमल और तीन साल की बेटी है।

बताया गया कि शिवम ने बीटेक की पढ़ाई पूरी की थी और घर पर ही बच्चों को कोचिंग पढ़ाकर परिवार का पालन-पोषण करते थे। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया।

संक्षेप

किराना स्टोर में 60 हजार की चोरी

जौनपुर। गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के दुधौरा बाजार में बीती रात चोरों ने एक किराना स्टोर को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर छत काटकर दुकान में घुसे और बिक्री के 50 हजार रुपये नकद समेत करीब 60 हजार रुपये का सामान चोरी कर ले गए। पीड़ति रामजियावन यादव निवासी समोधीपुर, थाना गौराबादशाहपुर ने 16 सितंबर बुधवार की शाम थाने में तहरीर देकर बताया कि उनकी किराना एवं जनरल स्टोर की दुकान थाना क्षेत्र के दुधौरा बाजार में दुकान है। 15 सितंबर, मंगलवार की देर रात चोरों ने छत काटकर दुकान में प्रवेश कर लिया ।चोर दुकान में रखी बिक्री की रकम लगभग 50 हजार रुपये नकद और करीब 60 हजार रुपये कीमत का किराना सामान उठा ले गए। बुधवार को दुकान खोलने पहुंचे तो छत कटी देखकर होश उड़ गए। तहरीर पर पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर लिया गया है।

तहसील दिवस पर विशेष कैम्प 19 को

जौनपुर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी को अवगत कराया है कि जनपद में 19 सितम्बर को आयोजित होने वाले तहसील दिवस पर ऐसे मतदाता जिनका नाम 10 अप्रैल 2026 को अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में किन्हीं कारणों से सम्मिलित होने से छूट गया है । उन मतदाताओं से फार्म–6 भरवाने, मतदाता सूची में विद्यमान किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन हो तो फार्म–8 भरवाने एवं मृतक, शिफ्टेड मतदाताओं के नाम विद्यमान निर्वाचक नामावली से अपमार्जन हेतु–7 भरवाने हेतु विशेष कैम्प आयोजित कराते हुए जनसामान्य में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना है एवं आयोजित कैम्प में प्राप्त होने फार्म–6, 7 एवं 8 का विवरण भी सायं 04 .00 बजे तक उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। यह भी अवगत कराया गया है कि प्रत्येक माह होने वाले तहसील दिवस पर मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में फार्म–6, 7 एवं 8 भरवाने हेतु कैम्प का आयोजन किया जाना है।

प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया गया

जौनपुर । लोहिया उद्यान पार्क में आज प्रधानमंत्री मोदी जी के 76वें जन्म दिवस पर जिला उद्यान अधिकारी द्वारा सीमा सिंह राणा के द्वारा 5001 दिया जलाकर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लगातार 25 साल बेमिसाल कार्य को याद किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प यात्रा निकाली गई । जिले में जगह–जगह पर दिया जलाकर प्रधानमंत्री की जन्मदिन को मनाया गया इस मौके पर गणमान्य व्यक्ति उद्यान अधिकारी सीमा सिंह राणा अंजना सिंह और भाजपा की सभी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए

प्रषिक्षण के लिए आवेदन 30 तक

जौनपुर। डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज आशुतोष सहाय पाठक ने अवगत कराया है कि अनुसूचित जातिध्जनजाति के व्यक्तियों को ट्रेड–ब्यूटी पार्लर में स्वरोजगार युक्त बनाये जाने हेतु सामुहिक प्रशिक्षण दिया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत 04 माह का प्रथम एवं द्वितीय बैच (45–45 अभ्यर्थियों) का प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसमें एक माह का सैद्धान्तिक एवं 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण होगा। अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान रू0 1250 .00 प्रतिमाह अभ्यर्थियों को मानदेय के रूप में दिया जायेगा।

स्टेडियम को 5000 दीपक से सजाया

जौनपुर। 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान के अन्तर्गत इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम सिद्दीकपुर में "आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम को मनाये जाने के अन्तर्गत खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग एवं नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में स्टेडियम परिसर को विभिन्न खेलों के प्रशिक्षणार्थियों एवं माई भारत कार्यकर्ता की देख–रेख में 5000 दीपक से सजाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुनील यादव 'मम्मन' प्रतिनिधि, अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत करंजाकला द्वारा कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राज कुमार यादव, शशि कुमार यादव, अमरजीत यादव, दिलीप कुमार, कृष्ण कुमार यादव, अशोक कुमार सोनकर, निलेश कुमार यादव, सुश्री मोना सिन्हा अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षक एवं मनोज यादव जिला व्यायाम प्रशिक्षक, युवा कल्याण विभाग द्वय द्वारा कीड़ा अधिकारी, जिला युवा कल्याण एवं प्रदेशिक विकास दल अधिकारी एवं समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र जौनपुर की देख–रेख में सम्पन्न कराया गया।

सेंध लगाकर चोरों ने दो लाख का माल उड़ाया

जौनपुर। नगर क्षेत्र में सिपाह पुलिस चैकी के भौंराजीपुर में आटा चक्की की दीवार में सेंध लगाकर करीब दो लाख रुपये चोरी किए जाने की घटना ने प्रकाश में आई है। इलाके में पुलिस गश्त को लेकर सुरक्षा व्यवस्था हेतु सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्य मार्ग के किनारे हुई इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों में भय के साथ चिंता का माहौल बना हुआ है। मोहल्ला भौंराजीपुर स्थित मैरिज हाल के बगल में वर्षों से संचालित हो रही आटा चक्की को हौसला बुलंद चोरों ने निशाना बनाया। संचालक राधेश्याम मौर्य के मुताबिक चोर दीवार की पटिया निकालकर चक्की के अंदर दाखिल हुए और रात में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। संचालक का यह भी दावा है कि सरसों की पेमेंट के लिए करीब डेढ़ लाख रुपये रखे थे, जबकि करीब 50 हजार रुपये पहले से चक्की में रखे हुए थे। उनके अनुसार हौसला बुलंद चोरो से लगभग दो लाख रुपये हाथ साफ कर दिया है। सुबह करीब 10 बजे पुलिस को घटना की सूचना दी गई।

जयपुर राज हाउस की दो कोठियों : यहीं बना था अंग्रेजों का सचिवालय, दंगों में ठहरी थी पीएसी, अब हैं सरकारी ऑफिस

आर्यावर्त संवाददाता

आगरा। जयपुर राजघराने की 100 बीघा में फैली संपत्ति जयपुर राज हाउस की दो कोठियों की अहमियत इतनी थी कि आजादी के तुरंत बाद हुए दंगों में इसकी सुरक्षा के लिए पीएसी के जवान तैनात किए गए। एक अप्रैल 1948 से 28 फरवरी 1949 तक जयपुर राज हाउस में मौजूद स्टेट जीएसटी के वर्तमान कार्यालय को जवानों के लिए बैरक का रूप दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने इसके लिए 3300 रुपये का किराया उस समय दिया था।

11 नवंबर 1954 को गृह विभाग के सहायक सचिव जीसी पांडे ने तत्कालीन इंस्पेक्टर जनरल को पत्र लिखकर बताया कि आगरा में जयपुर राज हाउस में 10वीं वाहिनी पीएसी की बटालियन रही है। तत्कालीन राज्यपाल की स्वीकृति से पीएसी के रहने के दौरान एक अप्रैल 1948 से 28 फरवरी 1949 तक की अवधि के लिए 3300 रुपये किराया तय किया गया। हर माह 300 रुपये का किराया इन बैरकों के लिए दिया गया था। उस दौरान यह किराया डीएम को आकस्मिक शुल्क के रूप में जमा कराया गया।

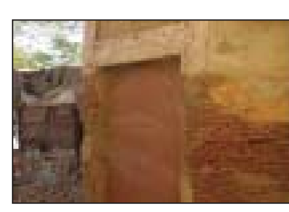

जयपुर हाउस में ही बना सचिवालय भवन

वर्ष 1836 में ब्रिटिश सरकार ने आगरा प्रेसिडेंसी की जगह नॉर्थ वेस्ट प्रॉविंस का गठन किया। तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल के लिए कोठी मीना बाजार में बनी फिदाई हुसैन की हवेली को तोड़कर निवास बनाया गया। इसी के नजदीक बने जयपुर हाउस में मौजूदा एडीए कार्यालय और स्टेट जीएसटी कार्यालय की कोठियों को ब्रिटिश सरकार का सचिवालय भवन बनाया गया था।

18 जनवरी 1954 को प्रदेश सरकार के सचिव केएन सिंह को आगरा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के प्रशासक ने अपने पत्र में इसका ब्योरा दिया है। उन्होंने लिखा कि जयपुर हाउस ब्रिटिश शासन की प्रांतीय सरकार का सचिवालय भवन रहा है। यहां नगर पालिका और आगरा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का कार्यालय एक साथ होना चाहिए। इन दोनों का प्रशासक एक ही अधिकारी है, ऐसे में दोनों कार्यालय जयपुर हाउस में स्थानांतरित कर दिए जाएं।

आरएसएस के सर सहकार्यवाह ने देखा था शिलापट

जयपुर हाउस निवासी और आरएसएस से जुड़े विजय गोयल ने बताया कि सात साल पहले सर सहकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल जयपुर राजघराने के शिलापट को देखने आए थे जो लोहामंडी थाने के सामने खतैना रोड के मोड़ पर लगा हुआ है। आंबेडकर विश्वविद्यालय के इतिहास विभागाध्यक्ष रहे डॉ. सुगम आनंद के शोध में छत्रपति शिवाजी महाराज से जयपुर हाउस का जुड़ाव बताया गया था। नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि नगर महापालिका के पास जयपुर हाउस की जमीन कब आई, इसका ब्योरा मांगा गया है। इससे जुड़े सभी दस्तावेज की जांच की जा रही है। राजस्व अभिलेखों के साथ पूरा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है।

एडीएम प्रशासन आजाद भगत सिंह का कहना है कि हम इस मामले में सभी स्रोतों से जानकारी जुटा रहे हैं। कई अभिलेख मांगे गए हैं। सभी तथ्य जुटाकर शासन को पूरा ब्योरा भेजा जाएगा।

1954 में गोदाम के रूप में किया इस्तेमाल

1954 से 1955 के बीच उत्तर प्रदेश सरकार को भेजे गए पत्रों में जयपुर हाउस के बारे में लिखा गया है कि यहां मुख्य भवन का उपयोग गोदाम के रूप में किया जा रहा है। यह दयनीय हालत में है। 20 साल से इसकी मरम्मत नहीं हुई। पीएसी के हटने के पांच साल के अंदर ही यहां दरवाजे और खिड़कियां गायब हो गए। जो थे, वह जर्जर हो चुके। फर्श गायब हो चुका है। जगह–जगह गड्ढे हैं, छतें टपक रही हैं और उन्हें तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है। ऐसा न होने पर भवन के गिरने की आशंका जताई गई। यहां अस्तबल की ओर दो भवन और नौकरों के लिए क्वार्टर थे, जिनकी मरम्मत नहीं की गई। इंजीनियरों से सर्वे कराया गया, जिसमें अकेले मुख्य भवन की उचित मरम्मत और उसे रहने योग्य बनाने के लिए लाखों रुपये का खर्च बताया गया है।

पति को मार डाला : एटा में पत्नी ने बेटा–बेटी संग मिलकर किया कत्ल, ई–रिक्शा में शव लेकर घूमे, फिर नहर में फेंका

आर्यावर्त संवाददाता

एटा। यूपी के एटा में प्लॉट बेचने पर मिले 15 लाख रुपये के विवाद में पत्नी ने अपने बेटे-बेटी और दो साथियों के साथ मिलकर पति उदयवीर (36) का गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपियों ने शव हजारा नहर में फेंक दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा कर आरोपी पत्नी संगीता, सौतेले बेटे अंशुल और गांव जोगामई निवासी चरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में शामिल नाबालिग सौतेली बेटी को पुलिस ने अभिरक्षा में लिया है। पांचवें आरोपी की तलाश जारी है। वारदात में प्रयुक्त ई-रिक्शा भी बरामद कर लिया गया है।

गांव लालपुर कल्याणपुर निवासी उदयवीर पत्नी संगीता और तीन बच्चों के साथ हीरा नगर में किराए के मकान में रहता था। संगीता ने पहले पति की मृत्यु के बाद उदयवीर से दूसरी शादी की थी। बच्चों में अंशुल और एक नाबालिग बेटी पहले पति से हैं। छह वर्ष की दूसरी बेटी उदयवीर से है।

पुलिस के मुताबिक, उदयवीर ने कुछ दिन पहले करीब 15 लाख रुपये में अपना एक प्लॉट बेचा था। इस रकम को लेकर उसका पत्नी संगीता से विवाद चल रहा था। आठ सितंबर की रात इसी विवाद के चलते पत्नी ने अपने बेटे-बेटी व साथियों के साथ मिलकर उदयवीर की हत्या कर दी।

उदयवीर के सात-आठ दिन तक गांव नहीं पहुंचने पर भाई अजब सिंह को चिंता हुई। संगीता से पूछने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने नगर कोतवाली में तहरीर देकर भाई के साथ अनहोनी की आशंका जताई। पुलिस ने हत्या समेत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस ने पत्नी संगीता को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सच्चाई उगल दी। पुलिस अब हजारा नहर में मृतक के शव की तलाश कर रही है। वहीं, पांचवें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। उदयवीर के शव की हजारा नहर में तलाश की जा रही है। पत्नी समेत अन्य आरोपियों को पकड़ लिया गया है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। - कीर्तिका सिंह, सीओ सिटी

जिस बेटे को कमाने के लिए रिक्शा दिलाया, उसी ने पिता की जान ले ली

पिता ने बेटे को कमाने के लिए करीब एक साल पहले रिक्शा दिलाया था। उम्मीद थी कि बेटा मेहनत कर परिवार का सहारा बनेगा लेकिन रुपये के विवाद ने रिश्ते को ऐसा मोड़ दिया कि बेटे ने ही पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। प्लाट बेचने से मिले करीब 15 लाख रुपये को लेकर चल रहे विवाद में मां, बहन और अन्य साथी को साथ लेकर वारदात की गई। हत्या के बाद शव ठिकाने लगाने के लिए आरोपी कई घंटे तक नहरों के चक्कर काटते रहे। पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को पकड़ा है। कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला हीरा नगर में किराये पर रह रहे उदयवीर का प्लाट के रुपये को लेकर पत्नी से विवाद चल रहा था। इसी बीच आठ सितंबर की रात बेटे अंशुल ने मां संगीता, बहन और साथी चरण सिंह की मदद से पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को ई-रिक्शा में रखकर ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़े। हत्या के बाद आरोपी पहले गांव छछैना स्थित नहर पर पहुंचे। वहां पुलिस की मौजूदगी देखकर शव को फेंकने की योजना बदल दी। इसके बाद वे अरथरा स्थित नहर पर पहुंचे और शव को उसमें फेंक दिया। पुलिस को मामले की जानकारी मिलने के बाद हजारा नहर में शव की तलाश कराई गई। पीएसी के गोताखोर भी लगाए गए।

पहले जहर देकर मारने की थी योजना

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी चरण सिंह करीब 14 साल से संगीता के संपर्क में था। संगीता ने उसे फोन कर जहर मंगाने को कहा था। हालांकि बाद में खुद फंसने के डर से उसने जहर नहीं दिया। इसके बाद व्हाट्सएप कॉल के जरिये हत्या करने और शव को ठिकाने लगाने के तरीके बताए गए। पुलिस के अनुसार इसके बाद हत्या की साजिश को अंजाम दिया गया।

छह जिलों के 13 गांव चकबंदी प्रक्रिया से बाहर, 16 साल से लंबित गांव में भी प्रक्रिया पूरी

आर्यावर्त संवाददाता

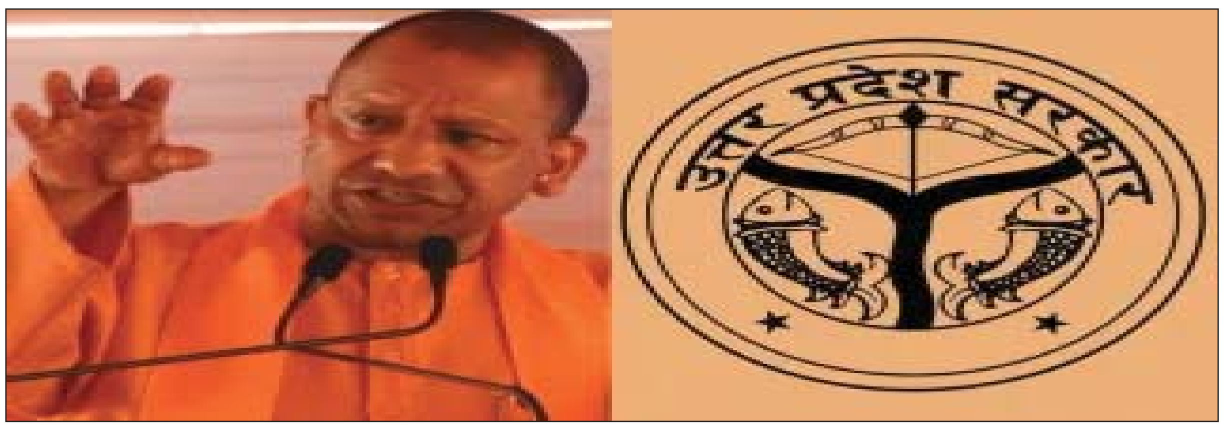

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में लंबे समय से लंबित चकबंदी प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा कराने की दिशा में चकबंदी विभाग ने महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। चकबंदी आयुक्त डॉ. ऋषिकेश भास्कर यशोद ने ऐसे गांवों को चकबंदी प्रक्रिया से अलग करने के निर्देश दिए हैं, जहां विभिन्न कारणों से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसका उद्देश्य किसानों को शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ ही भूमि संबंधी मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करना है।चकबंदी आयुक्त के निर्देश पर छह जनपदों के 13 गांवों को चकबंदी अधिनियम की धारा 6(1) के तहत चकबंदी प्रक्रिया से पृथक कर दिया गया है। इनमें जनपद मैनपुरी का गांव भांती शामिल है, जहां 35 वर्षों से चकबंदी प्रक्रिया चल रही थी। बदायूं के सिरतौल गांव में 14 वर्षों से, उन्नाव के दरौली, पीखी, सलौरी और निहालपुर गांवों में 12 वर्षों से, लखनऊ के शिवपुरी गांव में 12 वर्षों से तथा बरेली के कादरगंज गांव में 10 वर्षों से चकबंदी प्रक्रिया लंबित थी।इसी क्रम में बिजनौर के हसनवलीपुर और बैबलवाला गांव में दो वर्षों से तथा बदायूं के बक्सेना और इमलिया गांव में भी चकबंदी प्रक्रिया लंबित थी। इन सभी गांवों को चकबंदी अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रक्रिया से पृथक किया गया है।विभाग के अनुसार इन गांवों में चकबंदी प्रक्रिया लंबे समय से लंबित रहने के पीछे ग्राम विकास योजना के तहत आने, नदी के कटान से प्रभावित होने, चकबंदी योग्य क्षेत्रफल 40 प्रतिशत से कम होने, ग्राम के औद्योगिक विकास क्षेत्र में शामिल होने, गुटबंदी एवं दलबंदी जैसी परिस्थितियां प्रमुख कारण थीं। इन कारणों से प्रक्रिया को सुचारु रूप से आगे बढ़ाने में कठिनाई आ रही थी। विशेष प्रयासों के बावजूद कार्य आगे नहीं बढ़ पाने के कारण इन गांवों को चकबंदी प्रक्रिया से अलग करने का निर्णय लिया गया।इसके अलावा जनपद मुजफ्फरनगर के गांव पीपलशाह में 16 वर्षों से लंबित चकबंदी प्रक्रिया को विशेष प्रयासों के माध्यम से चकबंदी अधिनियम की धारा 52(1) के तहत पूर्ण कर दिया गया है। विभाग की इस कार्रवाई से लंबे समय से लंबित चकबंदी मामलों के निस्तारण में तेजी आने और किसानों को संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

प्रेम संबंधों के विवाद में रामकिशोर की हत्या, शव ठिकाने लगाने वाले तीन गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। मोहनलालगंज पुलिस ने रामकिशोर वाल्मीकि हत्याकांड का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त हथियार और घटना में इस्तेमाल ई-रिक्शा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार मृतक की हत्या प्रेम संबंधों को लेकर हुए विवाद के बाद की गई थी और शव को लकड़ी के बक्से में छिपाने के बाद ई-रिक्शा से ले जाकर नहर की पुलिया के नीचे फेंक दिया गया था।पुलिस के अनुसार 17 सितंबर को कविता देवी पत्नी रामकिशोर वाल्मीकि, निवासी छंदोइयाखेड़ा, थाना दुबग्गा की तहरीर पर पति रामकिशोर वाल्मीकि की हत्या कर शव छिपाने के संबंध में थाना मोहनलालगंज में मुकदमा अपराध संख्या 348/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 238 और 3(5) में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के अनावरण के लिए पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देश पर चार पुलिस टीमों का गठन किया गया।जांच के दौरान पुलिस टीमों ने घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा के आवागमन वाले मार्ग पर लगे करीब 170 से 180 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। तकनीकी और मैनुअल साक्ष्यों तथा स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा की पहचान की। इसके बाद 18 सितंबर को मो. इकबाल उर्फ वसीर अहमद, मुन्ना उर्फ मुच्छड़ और सूफिया बानो को गिरफ्तार किया गया तथा एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।पुलिस के मुताबिक पूछताछ में सूफिया बानो ने बताया कि उसके रामकिशोर वाल्मीकि से करीब चार वर्षों से प्रेम संबंध थे और लगभग दो वर्ष पहले दोनों ने निकाह कर लिया था। इसके बाद रामकिशोर उसके साथ रहने लगा था।

ओटीएस में गृहकर वसूली में लखनऊ नगर निगम प्रदेश में सबसे आगे

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। एकमुश्त समाधान योजना के तहत गृहकर वसूली में लखनऊ नगर निगम प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में सबसे आगे है। नगर निगम ने अब तक योजना के तहत 6.50 करोड़ रुपये की गृहकर वसूली की है। योजना के प्रति बकायेदारों में भी लगातार रुचि देखी जा रही है और बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। नगर निगम स्तर पर आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अब तक 3967 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 3723 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। पांच आवेदन निरस्त हुए हैं, जबकि 239 आवेदन अभी प्रक्रिया में हैं।

योजना के तहत पात्र बकायेदार 14 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदनों का निस्तारण और भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। महापौर सुषमा खर्कवाल ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना जल्द आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं।एकमुश्त समाधान योजना के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके लिए निर्धारित पोर्टल पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के लिए सबसे पहले पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर दिए गए 'ऑनलाइन आवेदन करें' विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों की सूची में से संबंधित नगरीय निकाय का चयन करना होगा। लखनऊ के बकायेदारों को नगर निगम लखनऊ का चयन करना होगा। इसके बाद सक्रिय दस अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज कर एक बार इस्तेमाल होने वाला संकेतांक प्राप्त करना होगा। मोबाइल पर प्राप्त छह अंकों के संकेतांक से सत्यापन के बाद आवेदन पत्र में संपत्ति पहचान संख्या, आवेदक का नाम और संपत्ति का प्रकार सहित आवश्यक विवरण भरकर आवेदन जमा किया जा सकता है। आवेदन जमा होने के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर से दोबारा प्रवेश कर उसकी स्थिति भी देखी जा सकती है।ऑनलाइन आवेदन के साथ ही ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। नगर निगम के सभी आठ जोन में एकमुश्त समाधान योजना के लिए सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहां नागरिकों को योजना से संबंधित जानकारी देने के साथ आवेदन प्रक्रिया में भी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। ऑफलाइन आवेदन जमा करने पर आवेदक को हस्ताक्षर और मुहर वाली प्राप्ति भी दी जाएगी।नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर एकमुश्त समाधान योजना के सॉफ्टवेयर और प्रक्रिया को लेकर नगर निगम मुख्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

जयंत चौधरी ने सपरिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की आत्मीय मुलाकात

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। भारत सरकार में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने अपनी धर्मपत्नी चारू चौधरी और पुत्रियों साहिरा एवं इलेशा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सपरिवार आत्मीय मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार जयंत चौधरी वर्तमान में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई इस मुलाकात में पारिवारिक आत्मीयता और सौहार्द का भाव देखने को मिला। मुलाकात के दौरान परिवार के सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री की सहज और आत्मीय बातचीत भी हुई।राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष व्यापार रोहित अग्रवाल ने इस आत्मीय मुलाकात पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जयंत चौधरी के बीच निरंतर संवाद देश में कौशल विकास, शिक्षा और युवाओं से जुड़े विषयों के लिए महत्वपूर्ण है।

युवाओं में अपार क्षमता, सकारात्मक दिशा में करें प्रतिभा और ऊर्जा का उपयोग : डॉ. बलजीत कुमार श्रीवास्तव

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में हिंदी प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित सप्त दिवसीय हिंदी कार्यशाला के अंतर्गत 18 सितंबर को 'युवा संवाद' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में राजभाषा सहायक निदेशक डॉ. बलजीत कुमार श्रीवास्तव उपस्थित रहे।डॉ. बलजीत कुमार श्रीवास्तव ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं में अपार क्षमता और प्रतिभा निहित है। अपनी क्षमताओं का सदुपयोग कर वे जीवन में बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो अथवा कोई अन्य क्षेत्र, आज भारत का युवा वैश्विक स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहा है। नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से युवा निरंतर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विगत कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में युवाओं ने नए उद्यम स्थापित कर देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि उन्हें केवल रोजगार की तलाश करने वाला नहीं, बल्कि रोजगार के अवसर सृजित करने वाला बनना चाहिए। युवाओं को शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान, उद्यमिता और रचनात्मक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए तथा अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का सकारात्मक दिशा में उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के भविष्य की जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है। इसलिए उनका दायित्व है कि वे अपने समय और सामर्थ्य का सदुपयोग करते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं और विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर प्रयास करें।कार्यक्रम के दौरान युवाओं की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए संवादात्मक सत्र भी आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों और शोधार्थियों ने मुख्य वक्ता से विभिन्न विषयों से जुड़े प्रश्न पूछे।

उत्तर प्रदेश में 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 400 करोड़ रुपये मंजूर

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े के आधुनिकीकरण और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 400 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में निगम के बस बेड़े को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दी गई है।शासनादेश के अनुसार इलेक्ट्रिक बसों की खरीद से प्रदेश में स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण और हरित परिवहन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों और शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। बसों की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, गुणवत्ता तथा निर्धारित मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।परिवहन निगम को योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करते हुए परियोजना को निर्धारित समय सीमा में क्रियान्वित करने को कहा गया है। शासनादेश के अनुसार 400 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के अतिरिक्त लगभग 25.50 करोड़ रुपये की शेष आवश्यकता का वहन परिवहन निगम अपने संसाधनों से करेगा।प्रदेश सरकार के इस निर्णय से यात्रियों को बेहतर, आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में हरित एवं सतत विकास के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में भी इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

50 हजार रुपये के इनामी प्लॉट जालसाज को मुंबई से गिरफ्तार, 32 मुकदमे दर्ज

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। निगोहां पुलिस और एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त टीम ने प्लॉट के नाम पर लोगों से रकम लेकर धोखाधड़ी करने के मामले में 50 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त राहुल श्रीवास्तव को महाराष्ट्र के ठाणे से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ लखनऊ के विभिन्न थानों में धोखाधड़ी और जालसाजी समेत 32 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी के कब्जे से आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 3050 रुपये नकद और दो आईफोन मोबाइल बरामद किए गए हैं।पुलिस के अनुसार 19 नवंबर 2025 को बलिया निवासी धर्मेन्द्र यादव ने थाना निगोहां में शिकायत दर्ज कराई थी कि राहुल श्रीवास्तव ने अपनी कंपनी के माध्यम से 1000 वर्गफुट प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के नाम पर विभिन्न माध्यमों से उनसे 3.50 लाख रुपये लिए थे। प्लॉट का कब्जा लेने पहुंचे तो पता चला कि संबंधित भूमि किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज है। आरोप है कि न तो प्लॉट का कब्जा दिया गया और न ही रकम वापस की गई। शिकायत के आधार पर थाना निगोहां में मुकदमा अपराध संख्या 213/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2) और 318(4) में मुकदमा दर्ज किया गया था।अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से गैर जमानती वारंट प्राप्त किया गया था। पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देशन में गठित टीम उसकी तलाश में जुटी थी। इसी क्रम में 16 सितंबर 2026 को निगोहां पुलिस और एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त टीम ने राहुल श्रीवास्तव को ठाणे, मुंबई से गिरफ्तार किया। ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करने के बाद 18 सितंबर को उसे थाना निगोहां लाया गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।पुलिस के अनुसार पूछताछ में राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि वह पहले राज हाईटेक कंपनी में ब्रोकर के रूप में काम करता था और बाद में बनारस में स्पीक एशिया कंपनी में एजेंट रहा। इसके बाद लखनऊ आकर उसने स्टैलियन विजन इंफ्रावेटर प्राइवेट लिमिटेड और एक्मे इंफ्रावेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनियां स्थापित कीं और स्वयं निदेशक रहा। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने विभिन्न लोगों को प्लॉट उपलब्ध कराने का भरोसा देकर अलग-अलग माध्यमों से धनराशि प्राप्त की। कई मामलों में प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के बावजूद वास्तविक कब्जा नहीं दिया गया और रकम भी वापस नहीं की गई।

संक्षेप

लकड़ी के बक्से में मिला युवक का शव, हत्या का मुकदमा दर्ज

लखनऊ। मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में पुलिया के नीचे लकड़ी के बक्से में शव मिलने के मामले में पुलिस ने हत्या समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 16 सितंबर 2026 को करीब तीन बजे मदारीखेड़ा मोड़, ग्राम भावाखेड़ा स्थित पुलिया के नीचे लकड़ी के बक्से में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने शव की शिनाख्त कराई, जिसमें मृतक की पहचान रामकिशोर वाल्मीकि पुत्र श्याम वाल्मीकि, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी छंदोइया खेड़ा, थाना दुबग्गा, कमिश्नरेट लखनऊ के रूप में हुई।मृतक के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोहनलालगंज में मुकदमा अपराध संख्या 348/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 238 और 3(5) में सोफिया बानो पत्नी अकरम, निवासी बिजनौर, लखनऊ तथा अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है।घटना के अनावरण और नामजद अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए पुलिस उपायुक्त दक्षिणी, कमिश्नरेट लखनऊ के निर्देश पर चार पुलिस टीमों का गठन किया गया है। गठित टीमें घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की गहनता से जांच कर रही हैं और नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी के साथ ही घटना के सफल अनावरण के लिए लगातार प्रयासरत हैं। मामले में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

बंथरा में घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, गले पर मिले चोट के निशान

लखनऊ। बंथरा थाना क्षेत्र के ग्राम खुर्रमपुर में 65 वर्षीय महिला की घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। महिला के नाक और मुंह से रक्त निकला हुआ था तथा गले पर चोट के निशान और रक्त लगा पाया गया। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है।पुलिस के अनुसार 18 सितंबर 2026 को सुबह करीब साढ़े आठ बजे थाना बंथरा को सूचना मिली कि ग्राम खुर्रमपुर में एक महिला अपने घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में पड़ी है। सूचना पर थाना प्रभारी बंथरा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घर चारों तरफ से बंद पाया गया और अंदर बिस्तर पर महिला का शव मिला। मृतका की पहचान छिदाना, उम्र करीब 65 वर्ष, पत्नी स्वर्गीय रामशंकर गौतम, निवासी ग्राम खुर्रमपुर, थाना बंथरा के रूप में हुई।घटना की सूचना पर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी ने अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया।

अजय राय ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन आयोजन और यूपीआई शुल्क को लेकर सरकार पर साधा निशाना

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हुए आयोजनों, बाढ़ की स्थिति, मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से हुई मौतों तथा यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगाए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर देश के कई हिस्से बाढ़ की तबाही से जूझ रहे हैं और लोगों को भोजन, पानी तथा दवाइयों की जरूरत है, वहीं प्रधानमंत्री का जन्मदिन बड़े स्तर पर मनाया गया और सरकारी धन की बर्बादी की गई।अजय राय ने कहा कि देशभर में करोड़ों दीपक जलाए गए और एक दीपक पर कम से कम पांच रुपये खर्च होने का अनुमान है। उन्होंने दावा किया कि दीपक जलाने के बाद बचा तेल कुछ गरीब बच्चे एकत्र कर रहे हैं। प्रेसवार्ता में उन्होंने एक वीडियो भी दिखाया, जिसमें एक बच्ची तेल एकत्र करते हुए दिखाई दे रही है और कथित तौर पर कह रही है कि इससे वह रात का खाना बनाएगी। अजय राय ने कहा कि जब गरीब परिवारों के पास खाना बनाने के लिए तेल और दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं, तब सरकार को ऐसे परिवारों के घरों में दीपक जलाने की व्यवस्था करनी चाहिए।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने वाराणसी में 500 बाइक दिए जाने का भी उल्लेख किया और आरोप लगाया कि बाइक चलाने वाले लोगों के साथ प्रतिदिन 700 रुपये देने का समझौता किया गया है।

न्यायालय से जारी वारंट के मामले में 12 साल से वांछित वारंटी गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। मानकनगर पुलिस ने न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट के अनुपालन में लंबे समय से वांछित वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम लगातार वारंटी अभियुक्त की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी। इसी क्रम में 18 सितंबर 2026 को पुलिस ने महेश कुमार प्रजापति, उम्र करीब 57 वर्ष, को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त महेश कुमार प्रजापति पुत्र स्वर्गीय मैकू लाल, निवासी 551झ/216 हरिहर प्रसाद नगर, रामनगर, थाना मानकनगर, लखनऊ के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 43/2012 में भारतीय दंड संहिता की धारा 454, 380, 448, 323, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज है। इस मामले में न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।मानकनगर पुलिस टीम द्वारा न्यायालय से जारी वारंट के अनुपालन में अभियुक्त की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही थी। संभावित ठिकाने पर दबिश के दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक त्रिभुवन सिंह और उपनिरीक्षक शाहिद खान, थाना मानकनगर, कमिश्नरेट लखनऊ शामिल रहे।

भाषा नहीं, राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है हिंदी : मंजूषा लखनऊ की विचार गोष्ठी में उभरा स्वर

लखनऊ। मंजूषा लखनऊ की ओर से उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहयोग से हिंदी दिवस की वर्तमान प्रासंगिकता विषय पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सभागार में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। दोपहर दो बजे से चार बजे तक चली गोष्ठी में साहित्य, पत्रकारिता और समाज से जुड़े अनेक गणमान्य लोगों ने भाग लिया। गोष्ठी की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार संजीव जायसवाल 'संजय' ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश साहित्यिक प्रतिष्ठान के प्रभारी संपादक दिनेश कुमार गुप्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एवं संयोजन अजय कुमार मिश्र ने किया।गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि जब एक तमिल भाषी और एक पंजाबी भाषी व्यक्ति हिंदी में संवाद करते हैं तो यह भाषाई एकता वास्तव में राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का काम करती है।

कक्षा छह से 12 तक की सभी छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने का निर्णय

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। किशोरियों के मासिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित सेवाओं को मजबूत करने तथा विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित राज्य स्तरीय मासिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठक शुक्रवार को एनेक्सी भवन, लखनऊ में अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित कुमार घोष की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और महानिदेशक परिवार कल्याण के साथ बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज, सूचना, नगर विकास, नमामि गंगे, श्रम, अल्पसंख्यक कल्याण, समाज कल्याण और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग तथा न्यूट्रीशन इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।बैठक में निर्णय लिया गया कि कक्षा छह से 12 तक सरकारी और निजी विद्यालयों में अध्ययनरत सभी छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों की छात्राओं के साथ विद्यालय न जाने वाली अथवा विद्यालय छोड़ चुकी किशोरियों तक भी निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था विकसित की जाएगी। समिति ने तय किया कि मासिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सेवाओं का लाभ प्रदेश की प्रत्येक किशोरी तक पहुंचाया जाएगा। इसमें विद्यालय से बाहर रहने वाली किशोरियों और वंचित समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विद्यालयों में मासिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन तथा किशोरावस्था से संबंधित शिक्षा और जागरूकता सत्रों को नियमित शैक्षणिक गतिविधियों का अभिन्न हिस्सा बनाया जाएगा।

मोदी को 'धमकाना' ट्रंप को पड़ा भारी!

कहने को तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि शायद वह मोदी को अब तक अच्छे से जान ही नहीं पाए हैं। देखा जाये तो जो लोग नरेंद्र मोदी को जानते नहीं, वह अक्सर धमकियों, प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव के सहारे उन्हें झुकाने का सपना देखते हैं। लेकिन मोदी का संकल्प साफ है कि भारत के हितों से समझौता नहीं होगा और देश को किसी विदेशी दबाव के आगे झुकने नहीं देना है। उनके हर फैसले में यही दृढ़ता दिखाई देती है। दूसरी ओर, ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही भारत पर दबाव बनाने के लिए शुल्क, व्यापारिक दबाव और रूस से तेल खरीद बंद कराने जैसी तमाम कोशिशें कीं, लेकिन नई दिल्ली ने हर बार अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च रखा। अब अमेरिका एक बार फिर टैरिफ रूपी आर्थिक हथियार लेकर मैदान में उतरा है, लेकिन मोदी सरकार ने भी बिना देर किए वाशिंगटन को साफ संदेश दे दिया है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हित किसी विदेशी दबाव की कीमत पर तय नहीं होंगे।

हम आपको बता दें कि जिस विधेयक को अमेरिकी कांग्रेस में पहली बार अप्रैल 2025 में पेश किया गया था, वह करीब डेढ़ साल तक अमेरिकी राजनीति और ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकताओं के बीच अटका रहा। लेकिन इस महीने यानि सितंबर 2026 में तस्वीर अचानक बदल गई। भारत में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ सक्रिय कूटनीतिक भागीदारी के कुछ ही दिनों बाद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने रूस और ईरान पर नए प्रतिबंधों वाला विधेयक पारित कर दिया। घटनाक्रम का समय भले ही संयोग हो, लेकिन संदेश बेहद स्पष्ट है कि वाशिंगटन रूस से जुड़े देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए अब शुल्क को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने को तैयार है।

लेकिन भारत ने भी अमेरिका को उसी क्षण जवाब दे दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा कि भारत अपने 140 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत बदलती बाजार परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग स्रोतों से ऊर्जा खरीदता रहेगा। इतना ही नहीं, नई दिल्ली ने अमेरिका को याद दिलाया कि इस कदम के भारत-अमेरिका संबंधों के साथ-साथ पूरे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के बारे में अमेरिकी पक्ष को पहले ही उच्च स्तर पर स्पष्ट रूप से बताया जा चुका है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने महत्वपूर्ण संदेश देते हुए कहा कि भारत अपने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। यानी अमेरिका शुल्क की धमकी दे सकता है, लेकिन भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा की कीमत पर किसी विदेशी दबाव के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है।

दरअसल, जिस विधेयक को अब 'लिंडसे ओ. ग्राहम रूस और ईरान प्रतिबंध अधिनियम 2026' कहा जा रहा है, उसकी कहानी डेढ़ साल पुरानी है। अप्रैल 2025 में लिंडसे ग्राहम और रिचर्ड ब्लूमेंथल ने रूस के खिलाफ कड़े प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिबंधों की पहल की थी। इसके बाद लंबे समय तक इसे कांग्रेस और प्रशासन के बीच समर्थन जुटाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। जुलाई 2026 में व्हाइट हाउस से सहमति बनने के बाद इसकी राह खुली। अगस्त में सीनेट ने इसे 86 के मुकाबले 11 मतों से पारित किया और 16 सितंबर को प्रतिनिधि सभा ने 262 के मुकाबले 159 मतों से इसे मंजूरी दे दी।

यह विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस के तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदारों पर सौ प्रतिशत तक शुल्क लगाने का अधिकार देता है। भारत और चीन इसके निशाने पर हैं। इसके पीछे अमेरिकी रणनीति रूस की ऊर्जा आय को चोट पहुंचाने की है, ताकि यूक्रेन युद्ध के लिए मास्को को मिलने वाले आर्थिक संसाधनों पर दबाव बनाया जा सके। विधेयक में रूस के ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों के साथ-साथ प्रतिबंधों से बचने वाले उसके जहाजी बेड़े पर भी शिकंजा कसने का प्रावधान है। लेकिन अमेरिका शायद यह भूल रहा है कि भारत रूस से तेल किसी राजनीतिक एहसान के लिए नहीं खरीद रहा। भारत की जरूरत है सस्ती, विश्वसनीय और लगातार उपलब्ध ऊर्जा। 2022 में रूस भारत के लिए कोई बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता नहीं था। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप द्वारा रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाए जाने से रूस का कच्चा तेल भारी छूट पर उपलब्ध हुआ और भारत ने अपने आर्थिक हित में इसे खरीदना शुरू किया। इसके बाद रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। वित्त वर्ष 2026 में भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूसी हिस्सेदारी 30.3 प्रतिशत रही और करीब 134.7 अरब डॉलर के कुल आयात में रूस से आने वाले तेल की कीमत 40.8 अरब डॉलर रही। जुलाई 2026 में तो भारत के आयातित तेल में रूसी हिस्सेदारी आधे से भी ज्यादा पहुंच गई।

वंदे मातरम को स्वीकार करने से भाग रही कांग्रेस

दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी इस नियति को स्वीकार करने से भाग रही है। जिस पार्टी ने आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया

एस. सुनील

वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों की राष्ट्रवाद की भावनाओं को प्रतीकित करने का माध्यम है। यह भारत की नियति का एक सबसे सुंदर हिस्सा है। दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी इस नियति को स्वीकार करने से भाग रही है। जिस पार्टी ने आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया, आजादी के 80वें वर्ष तक आते आते उसका इतना पतन हो गया कि उसने अपना ही इतिहास भुला दिया! आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस इतिहास को 1937 से शुरू करना चाहती है। लेकिन वंदे मातरम का इतिहास तो 1875 से शुरू होता है, जब महान बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने इसकी रचना की थी। इस गीत ने कई तरह के बदलाव देखे हैं। आजादी से पहले और आजादी के बाद की स्थितियां देखी हैं। अगर कांग्रेस इसे आजादी से पहले वाली स्थिति में ही रख कर देखना चाहती है तो यह उसकी समझ है। परंतु मौजूदा समय मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे किसी नेता के दबाव में निर्णय का नहीं है।

क्या कांग्रेस भूल गई कि 1896 के बाद से यह पूरा गीत कांग्रेस के अपने इतिहास का हिस्सा रहा है? स्वंय गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर ने 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम के सभी छह अंतरे गाए थे। 1896 से लेकर 1937 तक कांग्रेस के कम से कम सात राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम थे और उन सबकी अध्यक्षता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम के सभी छह अंतरे गाए गए। किसी मुस्लिम अध्यक्ष ने इस आधार पर आपत्ति नहीं की थी कि इसमें हिंदू देवी, देवताओं का जिक्र है और इससे उनकी धार्मिक भावना आहत होती है। शुरुआत 1896 से ही होती है, जब मोहम्मद रहमतुल्ला एम सयानी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और तब के कलकत्ता अधिवेशन में पूरा वंदे मातरम गाया गया था। ऐसे ही 1913 में कराची अधिवेशन में नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर कांग्रेस अध्यक्ष थे और पूरा वंदे मातरम गाया गया था। 1918 में उस समय के बॉम्बे में हुए विशेष कांग्रेस अधिवेशन में सैयद हसन इमाम कांग्रेस अध्यक्ष थे और वंदे मातरम के सभी छह अंतरे गाए गए। 1921 में हकीम अजमल खां और 1923 में मोहम्मद अली जौहर कांग्रेस अध्यक्ष थे और तब भी पूरे वंदे मातरम का गायन हुआ था। उसके बाद मौलान अबुल कलाम आजाद और मुख्तार अहमद अंसारी के समय भी वंदे मातरम को लेकर विवाद नहीं हुआ।

यह ऐतिहासिक तथ्य है कि मोहम्मद अली जिन्ना से पहले किसी मुस्लिम नेता ने धार्मिक भावना आहत होने के सवाल पर इस गीत का विरोध नहीं किया था। मुस्लिम नेताओं ने इस गीत का विरोध इसलिए नहीं किया था क्योंकि यह राष्ट्रवाद की भावना का गीत था, आजादी की लड़ाई का गीत था और साथ ही हिंदू व मुस्लिम के एक साथ मिल कर अंग्रेजों से लड़ने का गीत था। इस गीत और वंदे मातरम के नारे के साथ तो 1905 के बंग विभाजन का विरोध किया गया था और अंग्रेजों को बंगाल के बंटवारे का फैसला टालने के लिए विवश किया गया था। फिर यह कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने या किसी की भावना आहत करने वाला गीत हो सकता है? सबसे पहले इस गीत से मोहम्मद अली जिन्ना की भावना आहत हुई थी। वैसे उनकी भावना आहत होना भी एक राजनीतिक मसला था, जो उनकी महत्वाकांक्षा से जुड़ा था। उन्होंने मुस्लिम आवाम को कांग्रेस से दूर करने के लिए यह मुद्दा उठाया और उस समय कांग्रेस नेतृत्व ने आजादी की लड़ाई के व्यापक संदर्भ को देखते हुए यह समझौता किया कि वंदे मातरम के सिर्फ दो ही अंतरे गाए जाएंगे। तभी 1937 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार सिर्फ दो अंतरे गाए गए। हालांकि उसके बाद भी कांग्रेस मुस्लिम लीग को संतुष्ट नहीं कर पाई। इसका कारण यह था कि कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं को इस गीत के दो या चार अंतरे से समस्या नहीं थी। उनको वंदे मातरम के दो शब्दों से आपत्ति थी। उन्होंने अपने धार्मिक विश्वास को राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति का माध्यम बनाया और उसके बाद देश में क्या हुआ यह सब जानते हैं।

अगर कांग्रेस के इस तर्क को मान भी लें कि 1937 में महात्मा गांधी और दूसरे महान नेताओं ने जो वंदे मातरम गाया वही कांग्रेस गाएगी तब भी यह सवाल तो है कि क्या कांग्रेस अब भी मान रही है कि देश के हालात 1937 जैसे हैं? क्या कांग्रेस मान रही है कि नागरिकों का एक समूह देश के राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करना चाहता है तो उसकी मांग के आगे झुक जाया जाए? यह बहुत साफ दिख रहा है कि कांग्रेस अपनी तुष्टिकरण की राजनीति के चलते न सिर्फ राष्ट्रगीत का अपमान कर रही है, बल्कि कानून और संविधान का भी उल्लंघन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने संसद के मानसून सत्र में विधेयक पारित करके जो कानून बनाया है उसमें बहुत लचीलापन है। उसमें किसी को बाध्य नहीं किया जा रहा है कि वह पूरा वंदे मातरम गाए। राजकीय समारोहों में से पूरा बजाए जाने का प्रावधान किया गया है और नागरिकों से सिर्फ यह उम्मीद की जा रही है कि जब भी वंदे मातरम गाया या बजाया जाए तो वह उसका सम्मान करे। उससे सिर्फ यह उम्मीद की जाती है कि वह वंदे मातरम का अपमान नहीं करे, उसके गायन में बाधा नहीं उत्पन्न करे और इसे रोकने का प्रयास न करे। अगर उसे गीत याद नहीं है तब भी उससे सिर्फ सम्मान की उम्मीद की जा रही है।

असल में देश की मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा है अपनी संवैधानिक पहचान से ऊपर धार्मिक पहचान को रखना चाहता है। यह देश की एकता व अखंडता के लिए एक चिंताजनक विचार है। भारत का संविधान सबको धार्मिक आजादी देता है। लेकिन हर नागरिक की पहली पहचान भारतीय होने की है, जो संविधान से व्याख्यायित है। उससे ऊपर कोई पहचान नहीं हो सकती है। यह बात देश की मुख्य विपक्षी पार्टी को समझने की जरुरत है। नागरिक की संवैधानिक पहचान सबसे ऊपर है और अगर देश की संसद ने कानून बना कर वंदे मातरम का गायन अनिवार्य किया है और उसके सम्मान के कुछ नियम बनाए हैं तो उनका पालन किया जाना चाहिए। मुश्किल यह है कि कांग्रेस चित भी मेरी और पट भी मेरी की राजनीति कर रही है। उसने संसद में वंदे मातरम के विधेयक पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। उसको लग रहा था कि अगर उसने इसका समर्थन किया तो कट्टरपंथी मुस्लिम नाराज होंगे और अगर विरोध किया तो बहुसंख्यक हिंदू समाज के बीच नकारात्मक मैसेज जाएगा। इसलिए उसने रणनीतिक रूप से दूरी रखी। लेकिन बाद में कांग्रेस का असली रुप सामने आ गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा। जैसे ही वंदे मातरम का तीसरा अंतरा बजना शुरू हुआ सोनिया व राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तीनों असहज हो गए। सोनिया गांधी का तो चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा और उन्होंने सेवा दल के एक स्वंयसेवक को बुला कर नाराजगी जताई। साफ दिख रहा था कि वंदे मातरम का गायन रुकवाने का प्रयास किया जा रहा है।

व्यंग्य

अपने अनुसंधान क्यों नहीं कर सकतीं?

डीआरडीओ ने पारंपरिक मिसाइल क्षेत्र में जो तकनीकें विकसित की हैं, भारत सरकार ने उन सबको निजी कंपनियों को सौंपने को मंजूरी दे दी है। सवाल है, अपने अनुसंधान क्यों नहीं कर सकतीं?

भारत में 2001 में रक्षा क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया था। 2020 में इस क्षेत्र में ऑटोमैटिक रूट से 74 प्रतिशत और सरकारी मंजूरी के रास्ते 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत दी गई। अब तक 350 से ज्यादा निजी कंपनियों को उत्पादन लाइसेंस जारी किए गए हैं। लेकिन 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय सेना को निजी क्षेत्र से इतनी निराशा हुई कि लड़ाई के बाद बड़े सैन्य अधिकारियों ने इन कंपनियों की सार्वजनिक आलोचना की। वायु सेनाध्यक्ष ए.पी. सिंह ने कहा कि एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है, जो समय पर पूरा हुआ हो। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त यह पता नहीं होता कि वह समय पर पूरा होगा या नहीं। उन्होंने प्राइवेट कंपनियों से मुनाफे की सोच से ऊपर उठने का आह्वान किया था।

उप सेना प्रमुख राहुल आर. सिंह ने भी निजी रक्षा क्षेत्र को लेकर काफी हद तक एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह से मिलते-जुलते विचार जताए। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कहा कि अप्रैल 2025 में (ऑपरेशन सिंदूर से पहले) जब उन्होंने ड्रोन निर्माताओं से समय पर उपकरण देने की क्षमता पूछी, तो कई ने हाथ खड़े कर दिए। दोनों बड़े सैन्य अधिकारियों ने ध्यान दिलाया कि निजी कंपनियां रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च नहीं करना चाहतीं। अब भारत सरकार ने पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों पर सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने जो तकनीकें विकसित की थीं, उन सबको उन्हीं निजी कंपनियों को सौंपने को मंजूरी दे दी है।

ऐसा मिसाइल क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार खत्म करने का तर्क देकर किया जा रहा है। मगर निजी कंपनियां अपने अनुसंधान क्यों नहीं कर सकतीं? अगर उनमें इसको लेकर प्रतिस्पर्धा हो, तो भारत में ऐसे नए अस्त्र बनाए जा सकते हैं, जिनसे दुनिया अचंभित हो! लेकिन यह अनुभव दुनिया भर का है कि तुरंत मुनाफे की भावना से प्रेरित निजी क्षेत्र दीर्घकालिक महत्त्व के निवेश नहीं करता। ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र को रक्षा क्षेत्र में नेतृत्वकारी भूमिका निभानी पड़ती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे बेशुमार तजुर्बों से भारत में कुछ नहीं सीखा जा रहा है।

ब्लॉग

कांग्रेस हो या वामपंथी हर मायने में लाचार

हरिशंकर व्यास

यों कांग्रेस ही नहीं स्वतंत्र भारत ही एक श्राप का मारा है। इस श्राप का नाम है लेफ्ट, खासकर कम्युनिस्ट। इसने भारत की मूल सनातनी धर्म-पद्धति, सभ्यता और उसकी सहज सामाजिक चेतना को दीमक की तरह गलाया है। कैसे? याद करें तिलक-गोखले-गांधी की कांग्रेस को। स्वतंत्रता के समय वह ₹राम₹ का नाम लेती थी। कांग्रेस रामराज्य, गीता, प्रार्थना, सत्य, अहिंसा, सर्वधर्म समभाव जैसे सभ्यतागत प्रतीकों की प्रतीक थी। यानी गांधी और कांग्रेसजन भारतीय समाज की जीवित वास्तविकता—धर्म—में जीते थे। उसी के नैतिक बल से देश बनना था। गांधी की शब्दावली का अर्थ था—मैं अपनी हिंदू सभ्यता और आस्था में खड़ा होकर दूसरे धर्म का बराबर सम्मान करता हूं। ठिक ऐसे ही दूसरे छोर पर सावरकर और मदनमोहन मालवीय थे। इन दोनों के आईडिया में हल्का अंतर था। सावरकर ने राजनीतिक हिंदुत्व का विचार दिया। इसका कोर था-धर्मशास्त्रों की प्रामाणिकता की जगह बुद्धिवाद और विज्ञान पर जोर। छुआछूत और जातिभेद मिटाने की दृढ़ता। उनके हिंदुत्व में पितृभूमि-पुण्यभूमि (जैसे की योरोपीय देशों में भी फ़ादरलैंड) से राष्ट्रीयता की परिभाषा थी। वही मालवीय नैतिक-सांस्कृतिक पुनरुत्थान और आधुनिकता के संतुलन का सुधारवादी सनातनी विचार लिए हुए थे। सावरकर के लिए गाय उपयोगी पशु थी, मालवीय के लिए पूज्य। जाहिर है गांधी, सावरकर और मालवीय—तीनों के भारत में वह था जो आज के मोदी-शाह और संघ परिवार के राम-नाम वाले कथित हिंदू राष्ट्र में कतई नहीं है। सवाल है ऐसा कैसे हुआ? कैसे यह नौबत की हिंदुओं के मूल सनातन सत्य, धर्म, बुद्धिवाद-विज्ञान, सर्वधर्म समभाव की जगह झूठ, अंधविश्वास, अनैतिक राजनीति, जातिय-धर्म कलह के जाहिल कथित हिंदू राष्ट्र में आमजन सांस ले रहा है? मेरा दो टूक जवाब है—लेफ्ट ने पहले भारत की सभ्यतागत राजनीति को असहज और संदिग्ध बनाया। फिर उसी से, अंततः प्रतिक्रिया में संघ-भाजपा का हिंदू, राम पर एकाधिकार बना।

मतलब कम्युनिस्ट- वामपंथी के प्रभाव में कांग्रेस (नेहरू से शुरू) की सेकुलर अतिशयता बनी। धर्मनिरपेक्षता का वह बेसुरा राग बना जिसने लोकमानस में जहर घोला। हिंदू बनाम मुस्लिम, पहचान की राजनीति, जातिवाद वोट की आवश्यकता बनी और बनाई। इसकी अतिशयता ने हिंदुओं को लाठीधारी संघ की ओर धकेला। और फिर संघ तथा नरेंद्र मोदी-अमित शाह-योगी की अतिशयता ने हिंदूओं को ऐसा अचेतन, कुंभकर्णी बनाया जो यह भी सुध नहीं कि मनुष्य धर्म की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता-संस्कृति में सत्यमेव जयते क्या था? सर्वधर्म समभाव क्या था और वह क्या था जिसके अजूबे में इकबाल ने भी लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमाराж

मेरा मानना है कि इस सबके लिए जिम्मेवार देशी कम्युनिस्ट और वामपंथ है। भारत में वामपंथियों ने न केवल गांधी, उनके राम, और रामराज्य को नकारा बल्कि हर बात के लिए उस सनातनी जनमानस की बखिया उघेड़ी जो एक तरह से उसकी सभ्यता- संस्कृति-आस्था पर जूता मारना था। सोचे, जब सभ्यता-देश विशेष के मूलवासियों, बहुसंख्यको को ही यदि सांप्रदायिक करार दिया जाए, सरकार उसकी माईबाप बने और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) में 'संसाधनों पर पहला हक़ मुसलमानोंÓ जैसे वाक्य बोले तो इन सबकी अतिशयता का कुल जमा प्रभाव लोकमानस में क्या बनेगा? तब यह सोचना ही बेवकूफी है कि हिंदुस्तां के हिंदु अपने आपको असुरक्षित न माने। घर-घर मुसलमानों की चिंता न बैठ जाए। तभी कोई न माने इस बात को लेकिन मेरा मानना है कि 1947 के पहले हजार साला गुलामी के इतिहास में भी सनातनी मानस इतना डरा हुआ, असुरक्षित अपने को नहीं समझता रहा होगा जितना आज है, स्वतंत्र भारत में हो गया है!

यह संघ प्रोपेगेंडा की वजह से नहीं है बल्कि उस कांग्रेस की वजह से है जिसने 1947 से पहले निडरता, सर्व-धर्म समभाव का आत्मविश्वास दिखाया था। एओ ह्यूम की बनाई कांग्रेस में ढेरों कमियां थी लेकिन तिलक, जिन्ना, गोखले, मोतीलाल नेहरू, गांधी, सुभाष बोस, सरदार पटेल, नेहरू, डा राजेंद्रप्रसाद, मौलाना आजाद मोटामोटी आत्मविश्वासी, निर्भयी, सर्वधर्मं समभाव के सनातनी भाव में लोगों को जोडने वाले थे। कांग्रेस ने ज्यादा ही आत्मविश्वास दिखाया था इसलिए 1937 के बाद विभाजन की और जिन्ना व मुसलमान बढ़े। उसका आधार क्या था? उस साझा आत्मविश्वास का आधार धर्मो-जातियों का वह अनुभव था जिसमें जिसमें लाटसाहब जैसे अंग्रेज समाज में अब्दुला की शादी में बेगाने थे।

पूरा विषय विशाल है। कई पुस्तके लिखी जा सकती है। बुनियादी बात 1947 के बाद भारत की अपनी सीमा में आम हिंदू मनोभावों का सफर है। 1947 से 2026 की हिंदुओं की मोटामोटी पांच-छह पीढियों का अनुभव है। वह बहुत खराब रहा। तभी चौदह प्रधानमंत्री, चौदह सरकारों के निचोड़ में सनातनी, धर्म-जीवन पद्धति अब उस हिंदू में कनवर्ट में है जिसकी मुख्य चिंता मुसलमान है। उसी से भय, असुरक्षा तथा पराश्रय है। और यह नरेंद्र मोदी-अमित शाह-योगी आदित्यनाथ, संघ की वह राजनैतिक ताकत है जिससे आगे कांग्रेस हो या वामपंथी या क्षेत्रिय दल सभी हर मायने में लगातार लाचार है। कैसे इतनी लाचारगी? सोचे, कॉकरोच, जंतरमंतर आंदोलन, जनरेशन जेड की इस्टाग्राम-सोशल मीडिया पर प्रभुता के आम मायने क्या है? मोटामोटी नरेंद्र मोदी-अमित शाह, योगी, भाजपा-संघ की हवा बिगड़ने की वास्तविकताएं। मगर पहली बात, क्या ये राहुल गांधी, अखिलेश या प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव आदि की बदौलत है? कतई नहीं। जो हुआ है हवा जो बदलती लगती है उसकी वजह मोदी सरकार, भाजपा, संघ परिवार के अंहकार, उसकी बुद्धीहीनता है। मोदी सरकार ने प्रमाणित किया है लाठीधारी लोग विवेकी नहीं होते है। सत्ता का अंहकार यदि बुद्धीमान रावण को भी पतित, ठस, आत्मघाती बना देता है तो कुलियुगी अवतार और उसके अंधविश्वासी भक्त क्या बन जाते है यह 2026 के कथित हिंदू भारत, उसकी संस्थाओं के चेहरों की कथनी-करनी से लगातार जाहिर होता हुआ है।

सनातनी मानस राम और रावण की कथा में सांस लेता रहा है और वह मर्यादा बनाम अंहकार का फर्क बूझने की समझ लिए रहा है। बावजूद इसके यदि आज हिंदू भक्त रावणों के अंहकार को अपनी सुरक्षा, अपने भय (मुसलमानों, सेकुलरों, बुद्धी-विवेकी अर्थात बकौल मोदी दिमागी नक्सल) का निदान मानते है तो अनुमान लगाए कि कृष्ण मेनन,केडी मालवीय, पीएन हक्सर, नरूल हसन, राजेश्वरराव, गोपी अरोड़ा, मणिशंकर अय्यर, हरकिशनसिंह सुरजीत, सोनिया गांधी के एनएसी सलाहकारों, प्रकाश करात, और पिछले बारह वर्षो से कभी (दिवंगत) सीताराम यचूरी, कन्हैया, जयराम रमेश राहुल गांधी के दिल-दिमाग को जैसे लेफ्ट, प्रोग्रेसिव, कम्युनिस्टी जुमलों में भटका रहे है तो अस्सी साला इतिहास का सत्य क्या बनता है?

उपरोक्त एक पैराग्राफ स्वतंत्र भारत के अस्सी साला इतिहास का वह सार-संक्षेप है जिसकी गहराई, घटनाक्रम और तथ्यों को जितना जानेंगे, उतना समझ आएगा कि भारत राष्ट्र-राज्य का सनातनी हिंदू कितना और कैसे राम (मर्याद) रामराज्य, गांधी, सावरकर, मदनमोहन मालवीय के विचारों से भटका तो आत्मविवेक, सामान्य धर्म, नैमेत्तिक धर्म, कर्म, पुरषार्थ, स्वाभिमानी और निर्भयी, स्वालंबी जीवन की पूंजी को भी गंवा बैठा!

सवाल केवल यह नहीं है कि हिंदू कहां से कहां पहुंचा। बड़ा सवाल है कि उसे वहां पहुंचाने में स्वतंत्र भारत की सत्ता और उसके वैचारिक सलाहकारों ने क्या-क्या किया? किसने नागरिक को पहले सरकार का आश्रित बनाया, फिर अधिकारों का याचक और अंततः जाति-धर्म की पहचान में अपना हिस्सा खोजता टुक्रडखोड लाभार्थी बना दिया? तभी कम्युनिस्ट-वामपंथ का प्रभाव केवल धर्मनिरपेक्षता का सवाल नहीं है। वह राज्य, समाज, अर्थव्यवस्था और नागरिक—चारों के रिश्ते का सवाल बनता है। सोचे क्या और कैसा है आज का सनातनी? कोई सौ करोड लोग पांच सौ-हजार रू के लाभार्थी हो गए है। खैरात, रेवडियों और आरक्षण के लिए बिलबिलाते हुए। इसके दोषी नरेंद्र मोदी से ज्यादा सोनिया गांधी- एक्टिविस्टों से भरी एनएसी की बनवाई राजनैतिक शब्दावली है। अर्थात मेहनत, पुरुषार्थ, परिश्रम और स्वावलंबन के साथ नागरिक की जिम्मेदारी की जगह राजनीति के केंद्र में केवल 'अधिकारÓ और 'हकदारीÓ का आग्रह बनाया। अधिकार-आधारित हकदारी, सामाजिक न्याय, रोजगार गारंटी, भोजन का अधिकार, सूचना का अधिकार, वन अधिकार आदि-आदि। इनमें कई अधिकार अपने आप में जरूरी और न्यायसंगत हो सकते है; पर सवाल उनका होना नहीं, बल्कि, राजनीति, सिस्टम का पूरा व्याकरण अधिकार पाने और सरकार से पाने में सिमटने का है। नेहरू ने समाजवादी मॉडल में लोगों को राशन बांटना शुरू किया और सरकार को उद्यमी, पूंजी-धन अर्जन, टैक्स वसूली का माईबाप बनाया। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाने का नारा दे कर पीएन हक्सर, डी. पी. धर, जी. पार्थसारथी और सीपीआई के समर्थन-वाले सत्ता-विचार संसार में इंडिया को ही इंदिरा बना दिया। अधिकृत अवतार की पहला विमर्श इंदिरा गांधी के ही समय का है। फिर राजीव गांधी आए। कंप्यूटर-इक्कीसवीं सदी की लोगों को झांकी दिखाई। सोनिया गांधी के साथ झोपडियों में जाकर भारत की गरीबी देखी। दलालों को मिटाने का भाषण दिया। किसलिए? ताकि गरीब तक सरकार के सौ रूपएं में पंद्रह नहीं बल्कि पचास या सौ रूपए पूरे पहुंचे। मणिशंकर अय्यर, गोपी अरोडा जैसे प्रगतिशील तब भी गांधी की बचीखुची कांग्रेस से पुराने नेताओं को बाहर करवाते हुए थे। राजीव गांधी के आसपास आधुनिकतावादी, नौकरशाही और सेकुलर-प्रगतिशील सलाह का नया घेरा बना था। सो शाहबानू से मुस्लिम समाज की रियलिटी प्रकट हुई तो मुसलमानों की चिंता में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी सरकार ने दरकिनार किया। नतीजतन संघ-भाजपा को तुष्टीकरण का वह ब्रहास्त्र मिला जो आज तक जिंदा है और बारूद लिए हुए है। और यहीं स्वतंत्र भारत की सेकुलर राजनीति का वह अंतर्विरोध है जिसने कांग्रेस को खत्म किया, लेफ्ट-मध्यमार्गी नेताऔ के तीसरे मोर्चे की सरकारों के खत्म किया। लेफ्ट के प्रभाव में रही हर सरकार में समाज-सुधार का साहस केवल हिंदू समाज के लिए था वहीं अल्पसंख्यक धार्मिक नेतृत्व के सामने सावधानी या समर्पण! शाहबानो केवल एक मुस्लिम महिला के गुजारे-भत्ते का मामला नहीं था। उसने हिंदू मानस में यह सवाल बना—कानून और सुधार की कसौटी सबके लिए एक क्यों नहीं? कांग्रेस ने उत्तर देने के बजाय संतुलन साधा। और संतुलन साधते-साधते उसने संघ-भाजपा के हाथ वह राजनीतिक हथियार दे दिया जिसस उसने अगले चार दशकों में लगातार धार पाई। तथ्य है सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के समय के सबक गांठ में नहीं बांधे। तभी 2004 में कांग्रेस की सरकार बनने का समय आया तो अंबिका सोनी की जगह अहमद पटेल को उन्होने राजनैतिक सलाहकार बनाया। कांग्रेस-एनएसी- सरकार के बीच में सेतु, समन्वयक का दारोमदार अहमद पटेल पर था। उधर सरकार के समानांतर एनएसी में अधिकार-आधारित कल्याण, नागरिक समाज और एक्टिविस्ट राजनीति का दबदबा था।

मथुरा में बोरिंग के दौरान बड़ा हादसा, 11 हजार वोल्ट की लाइन से टकराया पाइप, 3 मजदूरों की मौत

आर्यावर्त संवाददाता

मथुरा। मथुरा जिले के शेरगढ़ थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम बोरिंग की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से तीन मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में चीख-पुकार मच गई। गुस्साए ग्रामीणों ने शवों को मौके पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।

बोरिंग का पाइप हाईटेंशन लाइन से छू गया

हादसा शेरगढ़ थाना क्षेत्र के प्यारा गांव में हुआ। बताया जा रहा है कि गुरुवार को गांव में बोरिंग की खुदाई का काम चल रहा था। इस दौरान गंगौरी गांव निवासी मजदूर मोहन और सुल्तान खुदाई का काम कर रहे थे। प्यारा गांव निवासी एक अन्य मोहन भी उनके पास खड़े थे। इसी दौरान बोरिंग का पाइप ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गया। पाइप में करंट उतरते ही वहां मौजूद तीनों लोग इसकी चपेट में आ गए। करंट लगने से तीनों गंभीर रूप से झुलस गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे के बाद मौके पर जुटे ग्रामीण

हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतकों के परिवार में भी कोहराम मच गया। ग्रामीणों और परिजनों में हादसे को लेकर आक्रोश है। उन्होंने तीनों शवों को मौके पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीण हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे

हादसे की सूचना मिलने पर शेरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। इसके बाद तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें शांत कराने में जुटे हैं। हादसे के कारण गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है।

हादसे की जांच में जुटा प्रशासन

पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और बोरिंग के दौरान सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे या नहीं, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में मातम है, जबकि गांव में ग्रामीणों का आक्रोश बना हुआ है।

दूबेपुर में निकली पोषण माह जागरूकता रैली, दिए पोषण के संदेश

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। जनपद में चल रहे 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत शुक्रवार को बाल विकास परियोजना दूबेपुर में पोषण जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को खंड विकास अधिकारी दूबेपुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम का आयोजन बाल विकास परियोजना अधिकारी दूबेपुर की अध्यक्षता में किया गया।

रैली में मुख्य सेविकाओं एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाथों में पोषण संबंधी संदेश लिखी तख्तियां लेकर कार्यकर्ताओं ने लोगों को संतुलित आहार, पर्याप्त पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा कुपोषण से बचाव के प्रति जागरूक किया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों को बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिए पौष्टिक आहार के महत्व की जानकारी दी। रैली के माध्यम से लोगों से पोषण को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और स्वस्थ समाज के निर्माण में सहयोग करने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में बाल विकास विभाग की मुख्य सेविकाएं एवं बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहीं।

संक्षेप

अपहरण के बाद घर पर धावा, फिर भी पुलिस मूकदर्शक

लम्भुआ/सुलतानपुर। अपराधियों के हौसले बुलंद हों और पुलिस कार्रवाई के नाम पर सिर्फ शिकायतों की फाइलें पलटती रहे, तो सवाल कानून-व्यवस्था पर ही उठेंगे। लम्भुआ कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर हरिवंश गांव में सामने आई घटनाओं ने पुलिस की कार्यशैली पर ऐसे ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पहले युवक का अपहरण हुआ, फिर धमकी दी गई और कार्रवाई न होने के बाद घर में घुसकर जान लेने की कोशिश की गई। बावजूद इसके पुलिस की कथित सुस्ती से परिवार दहशत में है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज शिकायत में पारसनाथ ने आरोप लगाया है कि 8 सितंबर 2026 को उनका पुत्र अनिल निषाद उर्फ पप्पू घास काटने गया था। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने कथित तौर पर उसका अपहरण कर लिया। शिकायत के मुताबिक उसे चांदा ले जाकर स्कॉर्पियो से वाराणसी के किसी जंगल में ले जाया गया। वहां अपहरणकर्ताओं के शराब पीने में व्यस्त होने का फायदा उठाकर युवक किसी तरह उनके चंगुल से निकल भागा और बाद में चरवाहों की सूचना पर बरामद हुआ। पीड़ित पिता के मुताबिक 10 सितंबर को लम्भुआ कोतवाली में शिकायत दी गई, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि इसके अगले दिन नामजद बताए जा रहे अशोक ने परिवार को धमकी देते हुए पुलिस से जांच कराने पर जान से मारने की बात कही। यदि शिकायत के बाद भी आरोपी बेखौफ घूमते रहें और पीड़ित को खुलेआम धमकाने का साहस करें, तो फिर पुलिस का खौफ आखिर किसके लिए है।यह सवाल ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

शाहगंज चौकी पर महिला होमगार्ड से अभद्रता का आरोप

सुलतानपुर। शाहगंज चौकी पर ड्यूटी में तैनात महिला होमगार्ड के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। महिला होमगार्ड ने चौकी पर तैनात सिपाही पर लघुशंका के लिए जाने से रोकने और विरोध करने पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। महिला होमगार्ड की शिकायत के बाद मामले को लेकर होमगार्ड संगठन में भी आक्रोश है। महिला होमगार्ड के मुताबिक उसकी ड्यूटी शाहगंज चौकी में लगी है। ड्यूटी के दौरान वह लघुशंका के लिए चौकी परिसर में बने बाथरूम की ओर गई। आरोप है कि वहां सिपाही वीरेंद्र कुमार यादव ने बाथरूम का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। महिला जवान का आरोप है कि बाथरूम में ताला भी लगा दिया गया था। जब उसने इसका विरोध किया तो सिपाही ने उसके साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया। घटना की जानकारी साथी होमगार्ड जवानों को हुई तो उनमें नाराजगी फैल गई। महिला होमगार्ड ने उच्चाधिकारियों को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं, होमगार्ड संगठन ने भी मामले को गंभीर बताते हुए पुलिस अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

यूजीसी व्यवस्था में बदलाव के विरोध में प्रदर्शन, आरक्षण में संशोधन की मांग

जयसिंहपुर/सुल्तानपुर। यूजीसी की प्रस्तावित नई नियामक व्यवस्था समेत उच्च शिक्षा और आरक्षण से जुड़े मुद्दों को लेकर शुक्रवार को परशुराम युवा वाहिनी और करणी सेना के संयुक्त बैनर तले पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बरौसा चौक पर धरना-प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर, पोस्टर और पंपलेट लेकर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। इसके बाद जुलूस तहसील परिसर तक पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित चार सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम जयसिंहपुर संदीप कुमार यादव को सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 को लेकर आपत्तियां जताईं। प्रस्तावित यूजीसी , एआईसीटीई और एनसीटीई की जगह नई नियामक व्यवस्था बनाने का प्रावधान प्रस्तावित है। विधेयक को दिसंबर 2025 में संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का उल्लेख करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस पर व्यापक चर्चा के बाद ही आगे बढ़ा जाना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अमित कुमार तिवारी ने कहा कि संगठन यूजीसी से संबंधित प्रस्तावित बदलाव को लेकर अपनी आपत्तियां सरकार तक पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा की नियामक व्यवस्था में बड़े बदलाव से पहले उसके प्रभाव, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और विभिन्न सामाजिक वर्गों के हितों पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।

शिक्षा जगत के एक युग का अवसान

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर/बल्दीराय। खंड शिक्षा अधिकारी श्याम बिहारी के स्थानांतरण के अवसर पर प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ बल्दीराय इकाई एवं विभिन्न शिक्षक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में बीआरसी सभागार बल्दीराय में भावभीनी विदाई सह सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के ब्लॉक अध्यक्ष एवं जिला महामंत्री पवन कुमार तथा ब्लॉक महामंत्री राजदेव यादव ने बीईओ श्याम बिहारी को अंगवस्त्र, माला पहनाकर, भारतीय संविधान की पुस्तक एवं विदाई सह सम्मान प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष राजबक्श मौर्य के नेतृत्व में पदाधिकारियों द्वारा भगवान बुद्ध की प्रतिमा एवं डॉ. भीमराव अंबेडकर का चित्र भेंट कर शुभकामनाएं दी गईं।

प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ द्वारा दिए गए प्रशस्ति पत्र में उल्लेख किया गया कि - शिक्षा जगत के एक युग का अवसान और आपके कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी सोच तथा शिक्षा के प्रति अटूट समर्पण को यह संघ नमन करता है। आपका बल्दीराय ब्लॉक में कार्यकाल केवल एक प्रशासनिक अवधि नहीं, बल्कि शिक्षा में गुणवत्ता, अनुशासन और मानवीय संवेदनाओं का स्वर्णिम अध्याय रहा है। अपने विदाई संबोधन में खंड शिक्षा अधिकारी श्याम बिहारी ने कहा कि बल्दीराय में बिताया गया समय उनके सेवाकाल का सबसे यादगार समय रहा। उन्होंने कहा कि यहां के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और कर्मचारियों ने हमेशा टीम भावना से कार्य किया। आप सभी ने जो सम्मान दिया है, उसे मैं जीवन भर याद रखूंगा। शिक्षा मित्र शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं और उनके सहयोग के बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना अधूरी है।

हरदोई में सो रही पत्नी की धारदार हथियार से हत्या, फिर खुद थाने पहुंचा पति, अवैध शक में ले ली जान!

आर्यावर्त संवाददाता

हरदोई। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के इस्लामनगर टिलिया में बुधवार तड़के महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान नगमा के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक, महिला की हत्या का आरोप उसके पति परवेज पर है। शुरुआती जांच में पत्नी के किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध होने के शक को हत्या की वजह बताया जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक, परवेज और उसकी पत्नी नगमा करीब डेढ़ महीने से इस्लामनगर टिलिया इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत या प्रेम-प्रसंग को लेकर पहले भी विवाद होता था। बुधवार तड़के दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि इसी दौरान परवेज ने धारदार चाकू से नगमा पर हमला कर दिया। हमले में महिला की मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी पति ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी।

हत्या के बाद खुद थाने पहुंचा पति

वारदात के बाद परवेज खुद शहर कोतवाली पहुंचा और पुलिस को पत्नी की हत्या की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, आरोपी पति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है।

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

हत्या की सूचना मिलने के बाद फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस अब हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार समेत दूसरे सबूतों की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से संबंध होने का शक सामने आया है। हालांकि, हत्या की वास्तविक वजह और वारदात की पूरी परिस्थितियों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी।

पुलिस सभी पहलुओं की कर रही जांच

पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि वारदात से पहले पति-पत्नी के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था। साथ ही पुलिस मृतका के परिजनों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतका के परिवार में भी मातम पसरा है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

बुलंदशहर में किसान की बेरहमी से हत्या, सिर पर धारदार हथियार के वार... सड़क पर मिला शव

आर्यावर्त संवाददाता

बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक किसान की हत्या से सनसनी फैल गई। शिकारपुर थाना क्षेत्र के रानाइच गांव में गुरुवार सुबह 45 वर्षीय किसान लालाराम का शव घर के पास गांव के मुख्य चौराहे पर पड़ा मिला। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, किसान के सिर पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। वहीं, शव की एक टांग कटी हुई मिलने की बात भी सामने आई है। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और फोरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए।

जानकारी के अनुसार, लालाराम बुधवार रात रोज की तरह खाना खाने के बाद सोने चले गए थे। परिवार के अन्य सदस्य भी घर में मौजूद थे। परिजनों के मुताबिक रात में सब कुछ सामान्य था। गुरुवार सुबह गांव के लोगों ने घर के पास रास्ते में लालाराम का शव पड़ा देखा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मामले की जांच के दौरान पुलिस को घर के अंदर कमरों और दरवाजे के आसपास खून के निशान मिलने की जानकारी मिली। इसके बाद घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। टीम ने अलग-अलग स्थानों से खून के नमूने और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं। घर के अंदर खून के निशान मिलने के बाद पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं।

पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लालाराम की हत्या आखिर किस जगह की गई। क्या हत्यारे ने घर के अंदर ही वारदात को अंजाम दिया और बाद में शव को बाहर ले जाकर फेंका? या फिर लालाराम को घर से बाहर बुलाकर उनकी हत्या की गई? पुलिस इस संभावना की भी जांच कर रही है कि कहीं हत्या के बाद शव को किसी दूसरे स्थान से लाकर घर के पास तो नहीं फेंका गया। इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि घर में मौजूद परिजनों को घटना की भनक क्यों नहीं लगी। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी दिनेश कुमार सिंह और एसपी देहात अंतरिक्ष जैन समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने परिवार के सदस्यों और आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। एसपी देहात अंतरिक्ष कुमार जैन के अनुसार, घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया है। घर के कमरों में भी खून के निशान मिले हैं। फोरेंसिक टीम ने खून के नमूने और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस हत्या के कारण, घटनास्थल और वारदात में शामिल लोगों की पहचान समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के नतीजों के बाद हत्या की परिस्थितियों को लेकर तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है।

मेरे सपनों का भारत में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा चित्रकला में साक्षी और भाषण में परी कौशल अव्वल

आर्यावर्त संवाददाता

बल्दीराय/सुलतानपुर। सेवा संकल्प अभियान-2026 के तहत 'मेरे सपनों का भारत' विषय पर क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में चित्रकला, लेखन एवं भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग करते हुए अपनी रचनात्मकता और विचार अभिव्यक्ति का प्रदर्शन किया।

श्री सिंहराय भालेसुल्तान इंटर कॉलेज, हलियापुर में आयोजित प्रतियोगिता में भाषण वर्ग में परी कौशल ने प्रथम, दिव्यांश सिंह ने द्वितीय और अंजलि सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। चित्रकला प्रतियोगिता में साक्षी प्रथम, प्रिया सरोज द्वितीय और अंशिका तृतीय रहीं। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। विजेता विद्यार्थियों को भाजपा जिला उपाध्यक्ष हिन्देश सिंह ने प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया। वहीं कैप्टन बालचंद्र इंटर कॉलेज, मीरपुर में भी चित्रकला, लेखन एवं भाषण प्रतियोगिताएं कराई गईं। विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा बूथ अध्यक्ष हरिप्रसाद मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य पवन कुमार यादव सहित शिक्षक अतुल मिश्रा, हेमंत पांडेय, शिवकुमार वर्मा, प्रमोद शुक्ला और अभिषेक सिंह मौजूद रहे।

उत्सव की आड़ में शोर का आतंक

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। त्योहार खुशियों के लिए होते हैं, लेकिन जब खुशी का शोर दूसरों की परेशानी बन जाए तो सवाल उठना लाजिमी है। धार्मिक महोत्सवों और वैवाहिक आयोजनों में बढ़ते हाई-बेस, हाई-वाइब्रेशन डीजे और तीक्ष्ण रोशनी को लेकर सुल्तानपुर में अब आवाज तेज होने लगी है। घर सुल्तानपुर फाउंडेशन ने इसे लेकर मुहिम छेड़ दी है, जिसे सोशल मीडिया पर व्यापक समर्थन मिलने का दावा किया जा रहा है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कराए गए ओपिनियन पोल में 85 प्रतिशत से अधिक नागरिकों ने हाई-वाइब्रेशन बीट और अत्यधिक तेज ध्वनि पर नियंत्रण की मांग का समर्थन किया। मुहिम में धार्मिक आयोजनों पर रोक की बात नहीं, बल्कि नियमों के दायरे में सीमित ध्वनि, सुरक्षित प्रकाश और अनुशासित आयोजन की मांग की जा रही है। दुर्गा पूजा, गणेश उत्सव, बारावफात, होली समेत विभिन्न आयोजनों में बड़े साउंड सिस्टम और भारी-भरकम डीजे की प्रतिस्पर्धा बढ़ने की शिकायतें सामने आती रही हैं। आयोजनों में तेज ध्वनि और हाई-वाइब्रेशन को लेकर बुजुर्गों, छोटे बच्चों और गंभीर मरीजों की परेशानी का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आस्था की आवाज मधुर हो सकती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा का शोर क्यों? इसी सवाल को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न वर्गों के लोगों ने प्रशासन से ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों का सख्ती से पालन कराने की मांग की है।

दुखद घटनाओं के बाद उठे सवाल

बीते वर्षों में शहर के प्रमुख आबादी वाले क्षेत्रों में आयोजनों के दौरान हुई कुछ दुखद घटनाओं के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने तेज डीजे व वाइब्रेशन को लेकर सवाल उठाए हैं। हालांकि किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण को केवल डीजे की ध्वनि से जोड़ने के लिए चिकित्सकीय जांच और प्रमाण जरूरी हैं, लेकिन इन घटनाओं ने तेज ध्वनि के संभावित स्वास्थ्य प्रभावों को लेकर चिंता जरूर बढ़ाई है।

अस्पतालों और घनी आबादी में हो विशेष नियंत्रण

मुहिम से जुड़े लोगों का कहना है कि अस्पतालों, घनी आबादी वाले क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों के आसपास ध्वनि पर विशेष नियंत्रण जरूरी है। उनका तर्क है कि त्योहार मनाने का अधिकार सभी को है, लेकिन किसी दूसरे नागरिक के स्वास्थ्य, नींद या शांतिपूर्ण जीवन का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

अधिवक्ताओं ने कहा नियमों का पालन हो

सामाजिक संस्थाओं से जुड़े अधिवक्ताओं ने भी अभियान का समर्थन करते हुए प्रशासन से ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों और न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की मांग की है।

कोच अटेंडेंट ही निकले चोर, ट्रेन की एसी बोगी में सो रहे युवक के गले से सोने की चेन निकाली, तोड़कर 3 हिस्सों में बांटे, अरेस्ट

आर्यावर्त संवाददाता

चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस के एसी कोच में सफर कर रहे यात्री के गले से सोने की चेन चोरी होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कोच में तैनात तीन अटेंडेंटों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। घटना यूपी के आंवला और बरेली कैंट के बीच की बताई जा रही है। यात्री की नींद खुलने पर उसने पास खड़े एक अटेंडेंट को पकड़ लिया और जीआरपी को सूचना दी। पूछताछ में मामला खुला तो पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बागपत जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले शेखर, गजब सिंह और अनिल कश्यप के रूप में हुई है। जीआरपी ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई सोने की चेन के तीन टुकड़े भी बरामद किए हैं।

दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर जोनापुर बापू कॉलोनी निवासी रोहित कुमार ने जीआरपी को बताया कि वह मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और परिवार के साथ दिल्ली में रहते हैं। वह 14010 चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस से दिल्ली से सीतापुर जा रहे थे। उनका रिजर्वेशन बी-वन कोच में सीट नंबर 24 पर था। थकान के कारण रोहित सीट पर सो गए। सुबह करीब पांच बजे आंवला और बरेली कैंट के बीच उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि गले में पहनी सोने की चेन गायब थी। इसी दौरान सीट के पास कोच अटेंडेंट शेखर खड़ा दिखाई दिया, जबकि दो अन्य युवक दरवाजे की तरफ जाते नजर आए।

रोहित को शक हुआ तो उन्होंने शेखर को पकड़ लिया। पहले शेखर मामले को लेकर गोलमोल जवाब देता रहा। यात्री ने तत्काल जीआरपी को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने और सख्ती से पूछताछ करने पर शेखर ने अपने दो साथियों के नाम बताए।

चलती ट्रेन से कूदकर भागा, फिर जीआरपी ने दबोचा

पूछताछ में शेखर ने बताया कि गजब सिंह और अनिल कश्यप उसके गांव के दोस्त हैं। आरोप है कि तीनों ने मिलकर यात्री के गले से चेन निकालने की योजना बनाई थी। चेन चोरी करने के बाद उसे लेकर तीनों अलग होने की कोशिश में थे।पुलिस के मुताबिक, ट्रेन की रफ्तार कम होने पर शेखर भी चलती ट्रेन से कूदकर भागने लगा। इसके बाद जीआरपी ने तलाश शुरू की और गश्त के दौरान तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लियापूछताछ में आरोपियों ने बताया कि चेन को चोरी करने के बाद करीब दस मिनट के अंदर ही उसके तीन टुकड़े कर लिए गए थे। तीनों ने चेन के हिस्से आपस में बांट लिए थे। पुलिस ने तीनों हिस्सों को बरामद कर लिया।

इस घटना के बाद एसी कोच में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। यात्री एसी कोच में सफर के दौरान खुद को ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। ऐसे में अगर कोच में यात्रियों की मदद के लिए मौजूद अटेंडेंट पर ही चोरी का आरोप लगे तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता होना स्वाभाविक है। जीआरपी अब आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि उन्होंने इससे पहले भी किसी ट्रेन या यात्री को निशाना बनाया था या नहीं।

जीआरपी प्रभारी इंस्पेक्टर एसके वर्मा ने बताया कि यात्री की सूचना पर तत्काल कार्रवाई की गई। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की गई सोने की चेन के तीनों टुकड़े बरामद कर लिए गए हैं। स्टेशन और ट्रेनों में अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्ती से कार्रवाई की जा रही है।

लाओस से कतर तकभारतीयों के लिए बदले इन 9 देशों के वीजा नियम, यात्रा से पहले जानें नया तरीका

अगर आप भी इस बार वेकेशन के लिए किसी इंटरनेशनल जगह का प्लान बना रहे हैं तो पहले वीजा नियमों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि अब 9 देशों ने अपने वीजा नियम में बड़ा बदलाव किया है।

भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए विदेश यात्रा अब थोड़ी बदल गई है। 2026 में कई देशों ने अपने वीजा नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिसका सीधा असर आपकी यात्रा की योजना पर पड़ेगा। कुछ जगहों पर अब ऑनलाइन वीजा (ई वीजा) की जरूरत होगी, जबकि कुछ ने भारतीयों के लिए पहले से आसान एंट्री के विकल्प खत्म कर दिए हैं। वीजा फ्री एंट्री, वीजा ऑन अराइवल और ई वीजा के बीच का फर्क समझना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।

पासपोर्ट इंडेक्स, जो दुनिया के पासपोर्टों की रैंकिंग करता है, उसने अपनी नई लिस्ट जारी की है। इसमें भारत 199 देशों में 73वें स्थान पर है। यह रैंकिंग बताती है कि भारतीय पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना वीजा या आसान वीजा प्रक्रियाओं के साथ यात्रा कर सकते हैं। 2025 की लिस्ट की तुलना में भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब चार और देशों के लिए वीजा लेना होगा। इसके साथ ही, पांच देशों ने भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी खत्म कर दी है, जो एक बड़ा बदलाव है।

किन देशों में क्या बदला?

लाओस और कतर ने वीजा ऑन अराइवल की जगह अब ई वीजा अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब है कि यात्रियों को अपनी यात्रा से पहले ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा और मंजूरी लेनी होगी, बजाय इसके कि वे वहां पहुंचकर वीजा प्राप्त करें। श्रीलंका ने भी ई वीजा ऑन अराइवल से बदलकर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन (ETA) लागू कर दिया है, जिसके लिए भी पहले से मंजूरी लेनी पड़ती है। ईरान ने नवंबर 2025 में ही वीजा ऑन अराइवल की सुविधा खत्म कर दी थी और अब ई वीजा की जरूरत होती है। ये सभी बदलाव यात्रा से पहले की तैयारियों को और महत्वपूर्ण बनाते हैं।

यात्रा से पहले करें पुष्टि

अच्छी खबर यह है कि कुछ देशों ने वीजा प्रक्रिया को आसान भी किया है। चिली, घाना और वेनेजुएला, जहां पहले सामान्य वीजा लेना जरूरी था, अब ई वीजा का ऑप्शन देते हैं। यह उन यात्रियों के लिए एक राहत की बात है जो इन देशों की यात्रा की योजना बना रहे हैं। वहीं, केप वर्डे ने 1 जनवरी 2026 से भारतीयों सहित 96 देशों के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा पूरी तरह खत्म कर दी है।

निकागुआ ने 14 फरवरी 2026 से भारतीय नागरिकों के लिए वीजा आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। आप या तो इलेक्ट्रॉनिक वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपना आवेदन फॉर्म निकारागुआ के इमिग्रेशन अधिकारियों को ईमेल से भेज सकते हैं। इन बदलावों से साफ है कि अपनी उड़ान बुक करने और होटल की बुकिंग करने से पहले लेटेस्ट एंट्री नियमों की जांच करना बहुत जरूरी है। एक ऐसा गंतव्य जहां आपने पुरानी लिस्ट में वीजा ऑन अराइवल देखा हो, वहां अब आपको यात्रा से पहले आवेदन करना पड़ सकता है। लापरवाही महंगी पड़ सकती है।

विदेश में मैराथन दौड़ का बढ़ा क्रेज, जानें क्यों लोग चुन रहे हैं 'रनकेशन'

आजकल छुट्टियां सिर्फ आराम करने या नई जगहें देखने के लिए नहीं होतीं। अब लोग अपने ट्रैवल प्लान्स में एक नया ट्विस्ट ढूंढ रहे हैं। अब ट्रैवल पसंद लोगों को सिर्फ मन की शांति नहीं बल्कि कुछ नया सीखने में भी दिलचस्पी बढ़ गई है। यही वजह है कि ट्रैवल के लिए नए-नए ट्रेंड भी सामने आ रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही ट्रेंड के बारे में बताएंगे। ये ट्रेंड है 'रनकेशन' का यह फिटनेस को ट्रैवल के साथ जोड़ता है, और इसका क्रेज तेजी से बढ़ रहा है।

रनकेशन यानी रनिंग और वेकेशन का मेल। इसमें आप सिर्फ घूमने नहीं जाते, बल्कि किसी खास मैराथन की तारीख के हिसाब से अपनी पूरी ट्रिप प्लान करते हैं। मंजिल पर पहुंचकर मैराथन की फिनिश लाइन पार करना ही आपकी छुट्टी का मुख्य मकसद होता है।

क्यों बढ़ रहा है इसका क्रेज?

गणपति ने कहा कि यह ट्रेंड खासकर युवा यात्रियों में ज्यादा दिख रहा है। उनके लिए फिटनेस, कम्युनिटी और पर्सनल माइलस्टोन अब ट्रैवल से जुड़ गए हैं। उन्होंने बताया कि मैराथन डेस्टिनेशंस के लिए एडवांस बुकिंग में 5 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है। गणपति ने इस ट्रेंड की खासियत बताते हुए कहा, "इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप पूरी ट्रिप को धावक के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। रेस से पहले शरीर को ढालना, रिकवरी का समय, खाने पीने की पसंद, लोकल एक्सपीरियंस और दूसरी जगहों पर घूमना सब कुछ प्लान में शामिल होता है। ऐसे में खेल इवेंट प्रेरणा देता है, और जगह आपको एक बड़ा अनुभव देती है।"

कौन सी जगहें हैं पसंदीदा?

कुछ शहर इस रनकेशन ट्रेंड में सबसे आगे हैं। गणपति ने बताया कि टोक्यो, बर्लिन, लंदन, न्यूयॉर्क और सिडनी जैसी जगहें बहुत पसंद की जा रही हैं। यहां आकर्षक रास्ते, सांस्कृतिक रूप से खास रेस अनुभव और एक खास अनुभव की उम्मीद लोगों को खींचती है।

भारतीय यात्रियों के लिए हालांकि पहुंचना एक बड़ी बात है। गणपति के अनुसार, जिन जगहों पर फ्लाइट कनेक्टिविटी अच्छी है, ट्रैवल टाइम कम है और जहां मैराथन के साथ बाकी जगहें भी घूम सकते हैं, वे ज्यादा लोकप्रिय हैं। उन्होंने बताया कि थाईलैंड उनकी रेस से जुड़ी सर्च में 2 5% हिस्सेदारी रखता है, इसके बाद वियतनाम और सिंगापुर हैं। इसके अलावा, 15 20% यात्री अपनी रेस प्लान के साथ कुछ और एक्सपीरियंस या जगहों के बारे में भी सर्च करते हैं।

क्या आप सोते समय बोलते हैं? जानिए ऐसा होने के 5 कारण

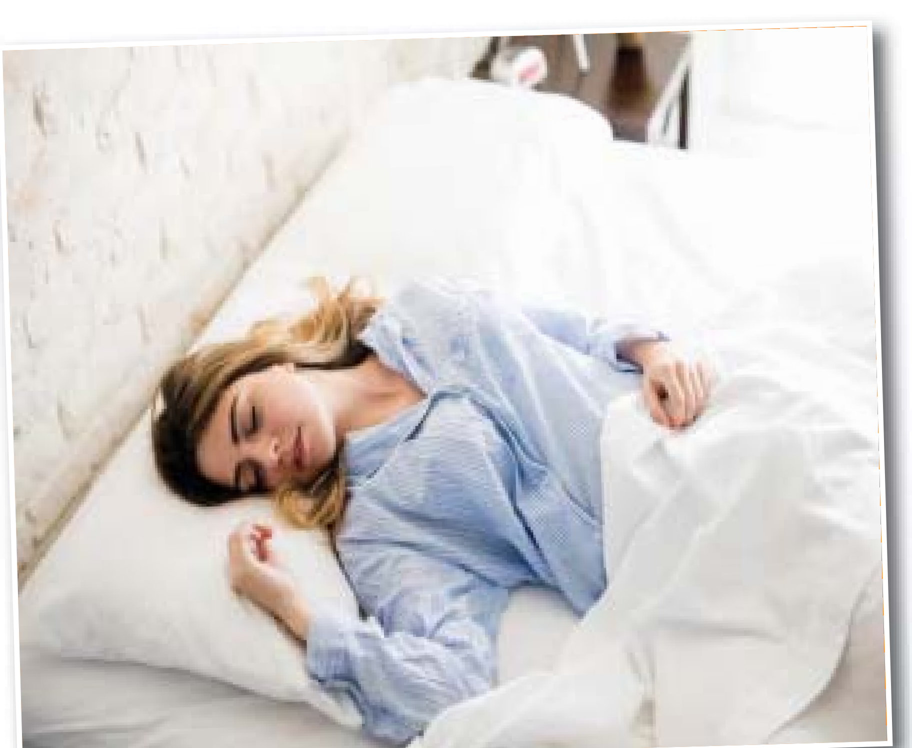

सोते समय बोलना एक आम समस्या है, जिसे अक्सर हल्के में लिया जाता है। हालांकि, यह समस्या कई लोगों के लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ प्रमुख कारण बताएंगे, जिनकी वजह से सोते समय बोलने की आदत पड़ सकती है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि कैसे इस समस्या से निजात पाया जा सकता है और इससे जुड़े मिथकों को तोड़ सकते हैं।

तनाव और चिंता

तनाव और चिंता सोते समय बोलने का एक प्रमुख कारण हो सकता है। जब हम दिनभर किसी समस्या या चिंता में उलझे रहते हैं तो रात को हमारी नींद भी प्रभावित होती है।

इस स्थिति में हमारा दिमाग शांत नहीं हो पाता और हम अनजाने में अपनी चिंताओं को बिस्तर पर व्यक्त कर देते हैं। इससे बचने के लिए दिनभर की चिंताओं को बिस्तर पर लाने से बचें और सोने से पहले कुछ देर ध्यान लगाएं।

सपने देखना

सपने देखना भी सोते समय बोलने का एक कारण हो सकता है। जब हम किसी सपने को बहुत गहराई से जीते हैं या उसका असर हमारे मन पर ज्यादा होता है तो हम अनजाने में उसे बिस्तर पर व्यक्त कर देते हैं।

इससे बचने के लिए अपने सपनों को समझने की कोशिश करें और अगर जरूरत हो तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लें, ताकि इस समस्या का समाधान हो सके।

मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं

कुछ मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, जैसे उदासी और गहरे तनाव आदि भी सोते समय बोलने का कारण बन सकते हैं। इन समस्याओं का असर हमारे मन पर गहरा होता है, जिससे हम अनजाने में अपनी भावनाओं को बिस्तर पर व्यक्त कर देते हैं।

इससे बचने के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, नियमित रूप से योग और ध्यान करें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ से सलाह लें, ताकि समस्या का समाधान हो सके।

शारीरिक असुविधा

शारीरिक असुविधाओं, जैसे दर्द या असुविधाजनक गद्दे का असर भी हमारी नींद पर पड़ता है, जिससे हम अनजाने में अपनी असहजता को बिस्तर पर व्यक्त कर देते हैं।

इससे बचने के लिए अपनी शारीरिक स्थिति का ध्यान रखें, आरामदायक गद्दे का उपयोग करें और नियमित रूप से व्यायाम करें, ताकि शरीर स्वस्थ रहे।

इसके अलावा दर्द होने पर चिकित्सक से संपर्क करें और उचित उपचार कराएं, ताकि समस्या का समाधान हो सके।

नशीले पदार्थों का सेवन

शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन भी सोते समय बोलने का कारण बन सकता है। इनका असर हमारी नींद पर गहरा होता है, जिससे हम अनजाने में अपनी भावनाओं को बिस्तर पर व्यक्त कर देते हैं।

इससे बचने के लिए इनका सेवन न करें और अगर जरूरत पड़े तो चिकित्सक से सलाह लें, ताकि समस्या का समाधान हो सके। इन कारणों को समझकर आप अपनी आदत पर नियंत्रण पा सकते हैं और बेहतर नींद ले सकते हैं।

चॉकलेट खाने के शौकीन हैं? इन 5 चीजों के साथ इसका स्वाद लगता है बेहतरीन

चॉकलेट एक ऐसा फ्लेवर है, जो हर किसी को पसंद आता है। खासकर बच्चों में तो इसका क्रेज देखने लायक है। अगर आप भी चॉकलेट के शौकीन हैं और रोजाना इसका सेवन करते हैं तो आइए आज हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जिनके साथ चॉकलेट का मेल खाने से इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही ये कई सेहत से जुड़े फायदे भी दे सकती हैं।

चॉकलेट और केले का मेल

चॉकलेट और केले का मेल एक बढ़िया संयोजन है। केले में पोटेशियम और फाइबर होता है, जो पाचन के लिए अच्छा होता है।

जब आप चॉकलेट के साथ केले को मिलाकर खाते हैं तो यह एक स्वादिष्ट और पोषक नाश्ता बन जाता है। केले की मिठास और चॉकलेट का हल्का कड़वा स्वाद एक साथ मिलकर एक खास अनुभव प्रदान करते हैं।

इसे आप फलों के सलाद में भी शामिल कर सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं।

चॉकलेट और बादाम का मिश्रण

चॉकलेट और बादाम का मेल भी एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। बादाम में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन होते हैं, जो त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं।

जब आप चॉकलेट के साथ बादाम को मिलाकर खाते हैं तो यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा होता है। इसे आप नाश्ते के रूप में खा सकते हैं या इसे मिठाइयों में भी शामिल कर सकते हैं।

चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी

चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी का मेल किसी भी मौके को खास बना सकता है। स्ट्रॉबेरी में विटामिन होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है।

जब आप चॉकलेट के साथ स्ट्रॉबेरी को मिलाकर खाते हैं तो यह एक अनोखा अनुभव प्रदान करता है। इसे आप मिठाई के रूप में भी खा सकते हैं या इसे किसी पार्टी में परोस सकते हैं।

इस संयोजन का मजा लेना न भूलें।

चॉकलेट और नारियल

चॉकलेट और नारियल का मेल भी एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। नारियल में फाइबर होता है, जो पाचन के लिए अच्छा होता है।

जब आप चॉकलेट के साथ नारियल को मिलाकर खाते हैं तो यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी लाभकारी होता है। इसे आप मिठाइयों में भी शामिल कर सकते हैं या इसे किसी पार्टी में परोस सकते हैं।

इसका आनंद लें और अपने नाश्ते को खास बनाएं।

चॉकलेट और कॉफी

क्या आप जानते हैं कि कॉफी और चॉकलेट का मेल भी बहुत अच्छा होता है? कॉफी में कैफीन होता है, जो आपको ऊर्जा देता है और चॉकलेट का हल्का कड़वा स्वाद इसे खास बनाता है। इसे आप सुबह-सुबह नाश्ते में ले सकते हैं या शाम की चाय के साथ भी इसका आनंद ले सकते हैं। इन सभी मेलों को आजमाकर देखें कि कौन-सा आपके लिए सबसे अच्छा है और अपने नाश्ते को खास बनाएं।

15 हजार करोड़ ट्रांजेक्शन, 60 करोड़ नए यूजर्स जुड़ेंगे, सरकार ने यूपीआई पर यूं ही नहीं लगाया चार्ज छिपी है ये स्ट्रैटजी?

यूपीआई के हर महीने 15 हजार करोड़ ट्रांजेक्शन का अनुमान

यूपीआई के बढ़ते दायरे के बीच सरकार रेवेन्यू मॉडल पर काम कर रही है। संसद की समिति ने आत्मनिर्भर मॉडल की जरूरत बताई थी। आइए इसे डिटेल में समझते हैं।

यूपीआई पेमेंट पर लगने वाले चार्ज को लेकर चर्चा तेज है। सरकार ने 2,000 रुपये से ज्यादा की मर्चेंट पेमेंट पर 0.14% MDR लगाने का फैसला किया है। इसी बीच संसद की वित्त पर बनी स्थायी समिति की 32वीं रिपोर्ट भी सुर्खियों में आई है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि आने वाले समय में UPI पर हर महीने 15 हजार करोड़ ट्रांजेक्शन हो सकते हैं और 60 करोड़ नए यूजर्स जुड़ सकते हैं। साथ ही समिति ने UPI के लिए आत्मनिर्भर रेवेन्यू मॉडल की जरूरत भी बताई थी। ऐसे में सवाल है कि आखिर सरकार ने चार्ज लगाने का फैसला क्यों किया और इसके पीछे की पूरी स्ट्रैटजी क्या है?

संसद में पेश हुई इस समिति की 32वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय को एक ऐसी राजस्व व्यवस्था तैयार करनी चाहिए, जिससे सरकारी खजाने पर बार-बार दबाव डाले बिना UPI को वित्तीय रूप से टिकाऊ बनाया जा सके। रिपोर्ट में समिति ने यह भी स्वीकार किया कि अगले तीन साल की प्रस्तावित योजना और कैशबैक जैसी व्यवस्थाएं मझोले और छोटे शहरों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए जरूरी हैं। खासकर उन इलाकों में जहां अभी तक डिजिटल पेमेंट की पहुंच पूरी तरह से नहीं बन पाई है, लेकिन इसके साथ ही समिति ने वित्तीय सेवा विभाग को यह भी सुझाव दिया है कि उसे एक आत्मनिर्भर राजस्व मॉडल तलाशने की दिशा में गंभीरता से काम करना होगा, ताकि योजना को लंबे समय तक बिना किसी वित्तीय संकट के चलाया जा सके। समिति की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि MDR की पूरी तरह अनुपस्थिति यानी जीरो-MDR व्यवस्था बैंकों और पेमेंट ऑपरेटरों के लिए वित्तीय रूप से टिकाऊ नहीं रह गई थी और यही वजह है कि अब चार्ज लगाने का फैसला लिया गया है।

15 हजार करोड़ तक पहुंचेगा ट्रांजेक्शन

समिति ने अपनी रिपोर्ट में आंकड़ों के जरिए इस समस्या की गंभीरता को भी सामने रखा। समिति के अनुमान के मुताबिक, आने वाले समय में UPI के जरिए हर महीने करीब 150 अरब लेनदेन होने की उम्मीद है और इस दौरान करीब 60 करोड़ नए यूजर्स इस नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि UPI का दायरा किस तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी दिक्कत भी सामने आती है। UPI को चलाने में बैंकों और पेमेंट कंपनियों का जो असली खर्च आता है, जैसे सर्वर, सिक्योरिटी, फ्रॉड रोकना और इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना, सरकार उसका सिर्फ 11 प्रतिशत हिस्सा ही सब्सिडी या इंसेंटिव के तौर पर भरती है। यानी हर 100 रुपये के खर्च में से सरकार सिर्फ 11 रुपये देती है। बाकी 89 रुपये का बोझ बैंकों और पेमेंट कंपनियों को खुद उठाना पड़ता है। इसी तरह, अगर सरकार UPI पर पहले जैसी सामान्य दर से MDR वसूलती, तो बैंकों और कंपनियों को जितनी कमाई होती सरकार अभी उसका सिर्फ 14 प्रतिशत हिस्सा ही "मुआवजे" के तौर पर दे रही है। सीधे शब्दों में कहें तो UPI मुफ्त है, लेकिन इसे चलाना महंगा है और सरकार जो मदद देती है वह असल खर्च और संभावित कमाई, दोनों के मुकाबले बहुत कम पड़ती है।

समिति ने आगाह किया था कि इसी असंतुलन की वजह से एक ढांचागत वित्तपोषण अंतर यानी फंडिंग गैप पैदा हो रहा है, जिसका सीधा असर आने वाले वर्षों में UPI से जुड़े बुनियादी ढांचे में होने वाले निवेश पर पड़ सकता है। समिति ने यह भी कहा था कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तेजी से पूंजी जुटाने, संभावित बड़े विलय और विदेशी निवेश आकर्षित करने की कोशिशों की वजह से सरकारी बैंकों के जरूरी कामकाज कमजोर न पड़ें, जिनमें प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कर्ज देना और कम मुनाफे वाली ग्रामीण शाखाओं को सेवाएं देना शामिल है।

अभी कितना बड़ा है यूपीआई का मार्केट

अब बात करते हैं कि आखिर भारत में UPI का नेटवर्क फिलहाल कितना बड़ा हो चुका है। मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में हर दिन करीब 66 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। सिर्फ जुलाई 2026 के महीने में ही करीब 2,366 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए, और इन लेनदेन की कुल रकम करीब 29.88 लाख करोड़ रही। यह आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि UPI अब सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश में हुए कुल डिजिटल पेमेंट में UPI की हिस्सेदारी 84 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो साफ दिखाता है कि UPI अब रोजमर्रा के डिजिटल भुगतान का सबसे अहम और भरोसेमंद जरिया बन चुका है।

कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार का यह कदम एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा नजर आता है। एक तरफ आम और छोटे ग्राहकों को 2000 रुपये तक के लेनदेन पर पूरी राहत दी गई है, वहीं बड़े और उच्च मूल्य वाले ट्रांजैक्शन पर मामूली शुल्क लगाकर सरकार इस विशाल नेटवर्क को दीर्घकालिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है। संसदीय समिति की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए यह साफ है कि आने वाले वर्षों में UPI का दायरा जितनी तेजी से बढ़ेगा, उतनी ही जरूरत इसके वित्तपोषण मॉडल को मजबूत बनाने की भी महसूस होगी, ताकि इस डिजिटल क्रांति की रफ्तार पर कोई असर न पड़े।

टाटा ग्रुप में आर-पार की लड़ाई, बाजार में लिस्टिंग रोकने पर अड़े नोएल

देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट घराने के हेडक्वार्टर बॉम्बे हाउस में वर्चस्व की पूरी तरह से खुली जंग छिड़ गई है। भारत के दिग्गज बिजनेस ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के बोर्ड ने अपने मौजूदा चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को फिर से नियुक्त किया है। लेकिन मेजॉरिटी शेयरहोल्डर टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने इस फैसले को 'अवैध' बता दिया है। गुरुवार को हुई एक तूफानी बोर्ड मीटिंग के बाद टाटा ग्रुप के भीतर का ये भारी मतभेद सबके सामने आ गया। एक तरफ चंद्रा की कुर्सी का सवाल है, तो दूसरी तरफ टाटा संस को शेयर बाजार में लिस्ट होने से रोकने की नोएल टाटा की लंबी जद्दोजहद है।

टाटा संस 125 अरब डॉलर वाले इस विशाल बिजनेस ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। इसकी बोर्ड मीटिंग में चंद्रशेखरन की वापसी का प्रस्ताव 4-1 के बहुमत से पास कर दिया गया। इस मीटिंग में नोएल टाटा ने अकेले इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। इसके तुरंत बाद टाटा ट्रस्ट्स ने सार्वजनिक तौर पर बयान जारी कर दिया। ट्रस्ट ने कहा कि चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति कानूनी रूप से शून्य (लीगल नलिटी) है। उनका तर्क है कि टाटा संस के नियमों (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के तहत ये फैसला मान्य नहीं है।

राहुल गांधी ने पीएम मोदी को 76वें जन्मदिन पर दी बधाई, जानिए क्या है कांग्रेस का आज का प्लान

दरअसल टाटा संस के बोर्ड में कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए टाटा ट्रस्ट्स के नॉमिनी की सहमति जरूरी होती है। मौजूदा बोर्ड में ट्रस्ट के सिर्फ दो नॉमिनी हैं- नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन। इन दोनों ने गुरुवार को अलग-अलग दिशा में वोट किया। नोएल ने खिलाफ वोट किया, जबकि वेणु ने समर्थन किया। जब मामला टाई होने की नौबत पर आया, तो मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हरीश मनवानी ने कास्टिंग वोट का इस्तेमाल किया।

टाटा संस के बोर्ड का मानना है कि उनका ये फैसला कानूनी रूप से सही है। लेकिन नोएल टाटा का कहना है कि उनका नेगेटिव वोट एक वीटो की तरह काम करता है, इसलिए मेजॉरिटी का फैसला अमान्य है। टाटा ट्रस्ट्स का कहना है कि उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की कानूनी राय भी पेश की थी, जिसे बोर्ड ने रिकॉर्ड पर नहीं लिया। ट्रस्ट ने ये भी कहा कि 12 अगस्त को चंद्रशेखरन ने खुद दोबारा पद न लेने का फैसला किया था, जिसे ट्रस्ट ने स्वीकार कर लिया था।

लिस्टिंग रोकने की बड़ी जद्दोजहद

इस पूरे विवाद के पीछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) का एक बड़ा फैसला भी है। हाल ही में आरबीआई ने टाटा संस की उस अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें कंपनी ने प्राइवेट बने रहने की मांग की थी। नियम के मुताबिक एक तय साइज के शैडो बैंकों को शेयर बाजार में लिस्ट होना जरूरी है। टाटा संस का बोर्ड आरबीआई की गाइडलाइंस का पालन करते हुए लिस्टिंग की तरफ कदम बढ़ाना चाहता है। नोएल टाटा का नजरिया इस पर बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि कंपनी को लिस्ट कराने की कोई मजबूरी नहीं है। उनका सुझाव है कि आरबीआई के नियमों का पालन करने के लिए कुछ अन्य स्ट्रक्चरल विकल्प तलाशे जा सकते हैं, जिससे टाटा संस को प्राइवेट रखा जा सके। मार्च 2024 में बोर्ड ने अनलिस्टेड रहने का जो फैसला किया था, उसे अभी तक औपचारिक तौर पर रद्द नहीं किया गया है। नोएल ने आरबीआई के फैसले को चुनौती देने के लिए कुछ और समय मांगा है। उन्होंने कहा है कि अगर लिस्टिंग जरूरी भी है, तो इसके लिए सितंबर 2029 तक का वक्त मिलना चाहिए।

कानूनी चुनौती से लेकर शेयरों की खरीद तक

कानूनी जानकारों का मानना है कि कंपनी एक्ट के तहत किसी नॉमिनी को चेयरमैन की नियुक्ति के पक्ष में वोट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कॉर्पोरेट वकील रुचि खतलावाला के मुताबिक, अगर टाटा संस के नियमों में वोटिंग की कोई खास शर्त अनिवार्य है, तो उसे पूरा न करने पर प्रस्ताव को चुनौती दी जा सकती है। ऐसे में सीधे 'अवैध' शब्द का इस्तेमाल जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन इस फैसले को कानूनी चुनौती जरूर मिलेगी।

अब सबकी निगाहें टाटा संस की एनुअल जनरल मीटिंग (एजीएम) पर टिक गई हैं। चेयरमैन बने रहने के लिए चंद्रशेखरन को एजीएम में डायरेक्टर के तौर पर दोबारा नियुक्त होना पड़ेगा। यहां असली पावर टाटा ट्रस्ट्स के पास है। फिलहाल सर रतन टाटा ट्रस्ट को फैसले लेने से रोका गया है, जिसकी वजह से कोरम पूरा न होने पर एजीएम टाल दी गई है। इसे 31 दिसंबर तक होना जरूरी है।

इसके अलावा नोएल टाटा ने शापूरजी पल्लोनजी (एसपी) ग्रुप की हिस्सेदारी खरीदने का एक विस्तृत प्रस्ताव भी रखा है। स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स कॉर्पोरेशन, सायरस इन्वेस्टमेंट्स के पास मौजूद हिस्सेदारी के बदले कम से कम 25,000 करोड़ रुपये की बात कही गई है। इस प्रस्ताव में 18 महीने के भीतर दो किश्तों में बायआउट की योजना है। इसके लिए एनसीएलटी के जरिए सिलेक्टिव कैपिटल रिडक्शन का तरीका अपनाया जा सकता है। नोएल ने सुझाव दिया है कि इसकी फंडिंग इंटरनल कैश फ्लो, लिस्टेड शेयरों की बिक्री, नए बिजनेस में निवेशकों को लाने से की जा सकती है।

लंदन से ढाका जा रही फ्लाइट में बवाल : पहले हुई बहस, फिर फिल्मी स्टाइल में मारपीट से मचा हड़कंप

ढाका, एजेंसी। लंदन से बांग्लादेश के ढाका जाने वाली एक फ्लाइट में हंगामा हो गया। दरअसल, दो यात्रियों के बीच झगड़ा हुआ और बात मारपीट तक पहुंच गई। यह घटना बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस है। अब सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है।

ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, लंदन से ढाका के लिए बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस की एक फ्लाइट ने उड़ान भरी। दो यात्रियों के बीच पहले बहस हुई और फिर वे आपस में लड़ने लगे। साथ के यात्रियों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों एक-दूसरे को लात-घूंसे मारने लगे। हालांकि, काफी मशक्कत के बाद उन्हें काबू में किया गया। इस घटना के दौरान एक यात्री की टी-शर्ट फट गई। बिमान बांग्लादेश ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। फ्लाइट में हुई बहस के बारे में पूछे जाने पर एयरलाइन के जनरल मैनेजर महबूबुद्दीन अहमद ने कहा, 'मुझे इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जल्द ही पता लगाऊंगा।' इसके साथ ही एयरलाइन ने घटना पर आगे कोई टिप्पणी नहीं की और इसमें किसी भी तरह की भूमिका से साफ इनकार कर दिया।

वहीं, जब दो यात्री आपस में झगड़ रहे थे, तो फ्लाइट में अफरा-तफरी मच गई। दूसरे यात्री डर गए थे। हालाकि, घटना के बारे में पता चलने पर पायलट तुरंत यात्रियों के पास पहुचे और स्थिति को शांत किया।

लाल सागर में बुरी तरह फंसा सऊदी, अमेरिका ने हूती लड़ाकों से कर ली सीक्रेट डील

वॉशिंगटन, एजेंसी। सऊदी अरब और हूती लड़ाकों के बीच चल रही लड़ाई में नया अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 दिन पहले वाशिंगटन के डिप्लोमेट्स और हूती के शीर्ष नेताओं के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में दोनों के बीच नए सिरे से डील की खबर सामने आई है। इस डील की खबर ने रियाद की टेंशन बढ़ा दी है।

द गार्जियन के मुताबिक अमेरिका और हूती ने 2025 के डील को रिन्यू किया है। हूती के लड़ाकों ने वाशिंगटन को भरोसा दिया है कि लाल सागर में उसके जहाजों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, जिसके बाद अमेरिका ने यमन में सऊदी को समर्थन न देने का फैसला किया है।

सऊदी ने मांगी थी अमेरिका से मदद

पिछले दिनों सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर मदद मांगी थी, लेकिन ट्रंप ने उन्हें कोई ठोस भरोसा नहीं दिया। इसके बाद अब जिस तरीके से यह खबर बाहर आई है, उसने रियाद की टेंशन बढ़ सकती है। सऊदी को अब तक पाकिस्तान, तुर्की और अमेरिका जैसे देश से कोई मदद नहीं मिली है। सऊदी ने अब हूती के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन, मिस्र और इजराइल से समर्थन मांगा है।

अमेरिका ने हूती लड़ाकों से डील क्यों की?

1। 2025 में वाशिंगटन ने हूती विद्रोहियों को आतंकी घोषित किया था। हूती लड़ाकों को खत्म करने के लिए यमन पर काफी बमबारी की। इसके बावजूद अमेरिका को सफलता नहीं मिली। आखिर में अमेरिका ने हूती विद्रोहियों से समझौता कर लिया। अमेरिका इस वक्त ईरान युद्ध में फंसा है, जिसके कारण होर्मुज से उसकी सप्लाई ठप है।

अमेरिका अगर हूती विद्रोहियों से लड़ता है तो लाल सागर में भी उसकी मुसीबत बढ़ सकती है। इसके अलावा हूती से लड़ने के लिए और अधिक खर्च करने होंगे। इस वक्त वाशिंगटन इस स्थिति में नहीं है।

2। हूती लड़ाकों की रडार पर सऊदी इसलिए है, क्योंकि रियाद यमन की सरकार को सैन्य सहायता मुहैया करा रहा है। यमन की जो सैन्य सरकार है, उससे अमेरिका को कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। इसलिए अमेरिका ने इससे पल्ला झाड़ लिया है। यमन में अमेरिका के पूर्व उप राजदूत नबील खौरी के मुताबिक ट्रंप प्रशासन और हूतियों के बीच एक तरह का मौन समझौता हो गया है।

खौरी का कहना है कि इस समझौते के तहत हूती अमेरिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और अमेरिका हूती को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।

रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में ये भारतवंशी सांसद, पार्टी के खिलाफ दिया वोट

वॉशिंगटन, एजेंसी। भारतीय-अमेरिकी सांसद कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति एकमात्र सांसद थे। जिन्होंने अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी से अलग हटकर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून के पक्ष में वोट दिया। 58 डेमोक्रेट सांसदों ने उस विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जिसमें रूसी तेल और गैस के शीर्ष पांच खरीदारों को 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रावधान है। इस कदम से भारत और चीन पर असर पड़ सकता है।

प्रतिनिधि सभा में छह भारतीय-अमेरिकी सदस्य हैं, जो सभी डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधियों रो खन्ना, प्रमिला जयपाल, अमी बेरा, थानेदार और सुहास सुब्रमण्यम ने पार्टी लाइन का पालन करते हुए उस विधेयक के खिलाफ मतदान किया जो रूस से

यूरेनियम की अमेरिकी खरीद को प्रतिबंधों के दायरे से छूट देता है। बुधवार को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एंड ईरान एक्ट' 262-159 के अंतर से पास हो गया।

यूक्रेनी समर्थक समूह से मुलाकात की

कृष्णमूर्ति, जिन्होंने मार्च में अमेरिकी सीनेट प्राइमरी का चुनाव लड़ा था लेकिन जीत नहीं पाए थे। अगले साल जनवरी में प्रतिनिधि सभा से सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इलिनोइस के कांग्रेसी सदस्य ने बुधवार को होने वाले मतदान से पहले एक यूक्रेनी समर्थक समूह से मुलाकात की।

मुलाकात के बाद क्या बोला?

उन्होंने बुधवार को 'इलिनोइस यूक्रेन एक्शन' के सदस्यों से मिलने के बाद एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'यूक्रेन के लोग अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए बहादुरी से संघर्ष कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। मैं इलिनोइस के यूक्रेनी समुदाय का आभारी हूं कि वे इस समर्थन को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

कृष्णमूर्ति उन मुखर भारतीय-अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों में से हैं जो अक्सर प्रवासी सदस्यों को सार्वजनिक पद की दौड़ में शामिल होने और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करते है।

पांच मिनट की गूगल मीट कॉल में 80 नौकरियां खत्म : अमेरिकी कंपनी ने पूरी भारतीय कस्टमर सर्विस टीम हटाई

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी ब्लू वाइन ने महज पांच मिनट की गूगल मीट कॉल में 80 लोगों की अपनी पूरी भारतीय कस्टमर सर्विस टीम को ही निकाल बाहर किया है। आर/इंडिया वर्कप्लेस कम्युनिटी में एक प्रभावित कर्मचारी ने अपना दर्द साझा करते हुए घटना की पूरी जानकारी दी है। कर्मी ने बताया कि छंटनी वाले दिन मैनेजमेंट ने सभी 80 कर्मचारियों को ऑपरेशनल कारणों (कामकाजी वजहों) का हवाला देकर ऑफिस आने के बजाय घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करने के लिए कहा था।

कर्मचारी अपनी शाम 6:30 बजे की सामान्य शिफ्ट कर रहे थे। शिफ्ट शुरू होने के ठीक 3 घंटे बाद, रात 9:30 बजे अचानक पूरी टीम को एक गूगल मीट लिंक के जरिये वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने को कहा गया। मीटिंग शुरू होते ही सीनियर

मैनेजमेंट ने बिना किसी पूर्व चेतावनी या नोटिस के सीधे तौर पर कह दिया कि पूरी भारतीय कस्टमर सर्विस टीम को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जा रहा है। यह पूरी बातचीत महज 5 मिनट में खत्म हो गई।

प्रबंधन ने कथित तौर पर प्रदर्शन से जुड़ी समस्याओं (परफॉरमेंस इश्यू) और अपेक्षाओं के अनुरूप आउटपुट न मिलने का हवाला दिया है। प्रभावित कर्मचारियों ने इन आरोपों को नकारा है और सोशल मीडिया पर अपनी निराशा व्यक्त की है।

अमेरिकी कंपनी डिजिटल बैंक और वित्तीय सेवा प्रदाता है। यह अमेरिका में छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायों को बैंकिंग, लोन और पेमेंट जैसी वित्तीय सेवाएं देती है। इस कंपनी का मुख्यालय न्यू जर्सी में है। कंपनी में वैश्विक स्तर पर करीब 1,000 कर्मचारी है। भारत में काम कर रही इसकी पूरी कस्टमर सपोर्ट यूनिट में 80 कर्मचारी थे, जिन्हें एक साथ इस कॉल के जरिये निकाला गया।

एक्सेस तुरंत ब्लॉक किया : जैसे ही 5 मिनट की गूगल मीट खत्म हुई, कर्मचारियों के ऑफिशियल ईमेल, स्लैक और कंपनी के अन्य सभी सिस्टम के एक्सेस तुरंत बंद कर दिए गए। उन्हें अपनी बात रखने का मौका भी नहीं मिला।

एआई बना छंटनी की वजह : कंपनी ने हाल ही में कॉल और ईमेल सपोर्ट के लिए एआई टूल्स को लागू किया था, जिसके बाद इंसानी कॉल्स के वॉल्यूम में 30% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई थी। बचे हुए काम को संभालने के लिए कंपनी ने किसी बाहरी थर्ड-पार्टी वेंडर को काम सौंप दिया है, जिससे उन्हें इन पक्के कर्मचारियों की जरूरत नहीं रही। प्रभावित कर्मचारी ने अपनी पोस्ट में लिखा, सभी 80 कर्मचारी।

पंजाब के बटाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के काफिले पर हमला, फेंके गए अंडे-टमाटर

बटाला। पंजाब के बटाला में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर हमला हुआ है। कुछ लोगों ने उनके काफिले पर अंडे और टमाटर फेंके। इस हमले के बाद बिट्टू ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और तीन हमलावरों को पकड़ने का दावा किया है। रवनीत सिंह बिट्टू पर बटाला के घासीतपुर गांव के पास हमला हुआ है। वह ड्रग्स के खिलाफ भाजपा की यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी बीच उनके काफिले पर हमला हुआ। कई लोगों ने अंडे और टमाटर फेंके। साथ ही, लोगों को नारेबाजी करते हुए देखा गया। बिट्टू ने दावा किया कि इस हमले में उनकी गाड़ी के शीशे भी टूटे हैं। घटनास्थल पर ही रवनीत बिट्टू ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, आज हमें ड्रग्स के खिलाफ एक यात्रा निकालनी थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार और ड्रग एडिक्ट्स सब मिले हुए हैं। वे पिछले साढ़े चार साल से यही कर रहे हैं। वहां करीब 500 लोग थे। मैं अपनी गाड़ी से उनके बीच से गुजरा। मेरे पास जेड-प्लस सिक्योरिटी है और मेरे साथ करीब 100 सुरक्षाकर्मी होते हैं। सुरक्षा के लिए स्थानीय डीएसपी और एसपी भी पुलिस के साथ वहां मौजूद थे।

उन्होंने तीन लोगों को पकड़ने का दावा करते हुए कहा कि इन लोगों को फोन जब्त कर लिए गए हैं। उनके फोन चालू हैं, जिन पर लगातार कहा जा रहा था कि उन्हें घेरो, उन्हें मारो, उनकी जान ले लो। उन्होंने गाड़ियों पर हमला किया और गाड़ियों की खिड़कियां तोड़ दीं। अंडे और टमाटर तो छोटी बात है। उनमें से कुछ के पास हथियार भी थे।

पासपोर्ट पर नया नियम लागू: 15 साल से कम उम्र के बच्चों का पासपोर्ट अब 5 साल तक रहेगा वैध

नई दिल्ली, एजेंसी। 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी होने वाले साधारण भारतीय पासपोर्ट अब पांच साल या बच्चे के 18 साल का होने तक, जो भी पहले हो, तक वैध रहेंगे। विदेश मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए नियमों के तहत यह बदलाव किया गया है। पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026, गुरुवार को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, जो पासपोर्ट नियम, 1980 को संशोधित करता है।

संशोधित नियम 12(1ए) के तहत, 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी किया गया 36 पन्नों वाला साधारण पासपोर्ट जारी होने की तारीख से पांच साल की अवधि तक, या बच्चे के 18 साल की उम्र पूरी होने तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा। 15 सितंबर की अधिसूचना में पासपोर्ट आवेदन शुल्क से संबंधित नियम 8 में भी संशोधन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आवेदन की प्रत्येक श्रेणी के लिए देय शुल्क नियमों की अनुसूची IV में निर्दिष्ट के अनुसार होगा।

संशोधित नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने 1 जुलाई से पासपोर्ट से जुड़ी सेवाओं के शुल्क में बढ़ोतरी की थी। बढ़ा हुआ शुल्क नए पासपोर्ट आवेदन, नवीनीकरण, तत्काल सेवाओं, खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले नए पासपोर्ट, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) और अन्य पासपोर्ट से जुड़ी सेवाओं पर लागू है।

बच्चों और वरिष्ठ जनों के लिए छूट रहेगी जारी

आठ साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी। हालांकि, यह छूट पासपोर्ट के पुनः जारी आवेदनों पर लागू नहीं होगी। वयस्कों के मामले में, 36 पन्नों वाले नए पासपोर्ट या नवीनीकरण के लिए सामान्य आवेदन पर शुल्क मौजूदा 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। 60 पन्नों वाले पासपोर्ट (वयस्क, सामान्य) के लिए शुल्क 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दिया गया है।

शुल्क में की गई बढ़ोतरी

तत्काल योजना के तहत 36 पन्नों वाले वयस्क पासपोर्ट के लिए शुल्क 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि इस श्रेणी में 60 पन्नों वाले पासपोर्ट के लिए शुल्क 4,000 रुपये से बढ़कर 6,000 रुपये हो गया है। तत्काल श्रेणी में 60 पन्नों वाले वयस्क पासपोर्ट के रिप्लेसमेंट के लिए शुल्क 5,500 रुपये से बढ़ाकर 8,500 रुपये कर दिया गया है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी पासपोर्ट सेवाएं महंगी हो गई हैं। नाबालिगों के लिए 36 पन्नों वाले नए या पुनः जारी (सामान्य) पासपोर्ट के मामले में, शुल्क 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,750 रुपये कर दिया। तत्काल श्रेणी में नाबालिगों के लिए 36 पन्नों वाले नए या पुनः जारी पासपोर्ट के मामले में, शुल्क 3,000 रुपये से 4,250 रुपये किया गया।

पकिस्तानी अभिनेता ने किया कैट का समर्थन, ट्रोलर्स को दिया जवाब, बोले- अपने भीतर सुधार करें

हाल ही में अंबानी के गणपति उत्सव में पहुंचीं कैटरीना कैफ को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। इसी बीच एक पाकिस्तानी अभिनेता ने कैट का समर्थन किया है।

अभिनेत्री कैटरीना कैफ की प्रगनेंसी के बाद वजन बढ़ने को लेकर पर सोशल मीडिया में तरह-तरह की बातें चल रही हैं। इसी बीच फिल्म 'मेरे ब्रदर की दुल्हन' में कैटरीना के को-स्टार रहे पाकिस्तानी अभिनेता अली जफर ने एक्ट्रेस का बचाव किया है।

अभिनेता अली जफर का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की ट्रोलिंग के बारे में बात कर कहे हैं। उन्होंने कहा, 'एक व्यक्ति मेरी को एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहा था। जिनके साथ मैंने पहले बॉलीवुड में काम किया था और वह उनकी प्रेगनेंसी के पहले के चेहरे और बाद के चहरे तुलना कर रहा था।

खासकर एक पुरुष होने के नाते, मेरा मानना है कि हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपने भीतर कुछ जरूरी सुधार करने की आवश्यकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जब किसी महिला की छवि की बात आती है तो उसका शरीर, उसकी सोच और जीवनशैली अगर वह हमारे द्वारा बनाए गए मानकों के अनुरूप नहीं है, तो हम उस पर बात करना शुरू कर देते हैं।

अली ने कहा यह बहुत गलत

आगे अपनी बातचीत में अली जफर ने कहा, 'यह गलत है, हर व्यक्ति अपने संघर्षों और अपनी खोजों से गुजर रहा है। हमें नहीं पता कि कोई अपने जीवन में क्या-क्या झेल रहा है। हमें लोगों के प्रति दयालु, सहानुभूतिपूर्ण, समझदार, स्वीकार करने वाला, सराहना करने वाला और सकारात्मक होना चाहिए। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हर महिला का अपना जीवन होता है। वह चाहे जिस भी खोज या संघर्ष से गुजर रही हो, उसका अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, उसका वर्तमान और भविष्य चाहे जैसा भी हो, यही उसका जीवन है। उसे जीने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? यह उसका जीवन है।'

क्या है मामला?

अंबानी परिवार के गणेशोत्सव में कई सेलेब्स पहुंचे।

इनमें विक्की कौशल और उनकी पत्नी कैटरीना कैफ भी शामिल थीं।

इस दौरान एक्ट्रेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं।

इन तस्वीरों और फोटोज में कई यूजर्स ने अभिनेत्री को उनके बढ़ते वजन को लेकर ट्रोल किया।

कई उनके लुक में कमियां निकाल कर उन्हें ट्रोल करने लगे।

इसके बाद कई सेलेब्स कैटरीना के समर्थन में उतरे।

सोमी अली, शिवालिका ओबेरॉय और राजीव अदातिया समेत कई कलाकारों ने उनका समर्थन किया।

स्टिक के सहारे चलते दिखे जहीर इकबाल, सोनाक्षी बोलीं-यह मैंने नहीं किया; यूजर्स ने कही ये बात

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अक्सर अपने फनी कंटेंट और एक दूसरे के साथ प्रैंक करने के चलते फैंस के बीच चर्चाओं में रहते हैं। दोनों अक्सर अपने वीडियोज पोस्ट कर फैंस को एंटरटेन करने का मौका नहीं छोड़ते। उनके इन वीडियोज पर फैंस भी जमकर प्यार बरसाते हैं। अब जानिए इस नए वीडियो में क्या खास है।

दरअसल, सोनाक्षी और जहीर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कपल गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंचा है। इस दौरान जहीर पैर में चोट होने के चलते स्टिक के सहारे चलते दिखे।

ब दोनों फोटो के लिए पोज देने खड़े होते हैं, तो सोनाक्षी मजाकिया अंदाज में जहीर की चोट पर इशारा करते हुए कहती हैं कि ये मैंने नहीं किया है। इसके बाद दोनों दर्शन करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं।

यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन

अब दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कई यूजर्स इस वीडियो पर काफी मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं।

एक यूजर ने जहीर के चलने के तरीके को फिल्म 'वेलकम' से जोड़ कर कमेंट किया, 'मेरी एक टांग नकली हे में हॉकी का बहोत बड़ा खिलाड़ी था एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पे गुस्सा आ गया और मेरी हॉकी से मेरे टाँग के दो टुकड़े कर दिए।' वहीं दूसरे ने मजाक में लिखा, 'सोनाक्षी ने टांग तोड़ी होगी...उसका बहुत मजाक उड़ाता है ये।

इसके अलावा कई यूजर्स ने जहीर की चोट पर चिंता जाहिर करते हुए इसकी वजह के बारे में पूछा। वहीं कुछ यूजर्स ने सोनाक्षी को उनके लुक के लिए तारीफ की।

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है कपल

बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफी प्रैंक्स करते हैं और एक दूसरे के वीडियोज पोस्ट करते रहते हैं। यूजर्स भी कपल के इन वीडियोज पर जमकर प्यार बरसाते हैं।

अपने रिटायरमेंट की खबरों पर बिग बी ने दी सफाई, बोलें- मैं काम से रिटायर नहीं हो रहा हूं

महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों 'केबीसी 18' होस्ट कर रहे हैं। वहीं व्यक्तिगत रूप से नह ब्लॉग के जरिए फैंस से जुड़े रहते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने रिटायरमेंट की इच्छा जताई थी। अब इस पर एक्टर ने अपनी बात रखी है।

उनकी रिटायरमेंट से जुड़ी खबरें आने के बाद बिग भी ने अपना अगला ब्लॉग इसी पर लिखा। उन्होंने स्थिति साफ करते हुए कहा, 'जी नहीं हुजूर, मैं काम से रिटायर नहीं हो रहा हूं। इसका मतलब था कि मैं सोने जा रहा हूं, और वहां आपको आने की अनुमति नहीं है।'

शो को होस्ट करना बताया था मुश्किल

अमिताभ बच्चन ने अपने पुराने ब्लॉग में लिखा था, 'कुछ प्रतिभागी इतनी गंभीर निजी कहानियां लेकर आते हैं कि न सिर्फ उनके लिए अपनी भावनाओं को संभालना, बल्कि शो को होस्ट करते रहना भी मुश्किल हो जाता है। मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इससे चैनल और होस्ट के बीच कुछ गलतफहमी हो सकती है। मगर यह अनुभव दिल तोड़ने वाला रहा है।'

'केबीसी 18' के बारे में

'कौन बनेगा करोड़पति' क्विज शो सोमवार से शुक्रवार रात नौ बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन प्रसारित होता है। इस शो की शुरूआत ब्रिटिश शो 'हू वॉन्ट्स टू बी अ मिलियनेयर?' के भारतीय वर्जन के रूप में हुई थी। 'केबीसी' से अमिताभ बच्चन ने टीवी पर पहली बार डेब्यू किया था। अमिताभ बच्चन को शो के होस्ट के रूप में दर्शकों ने खूब प्यार दिया।

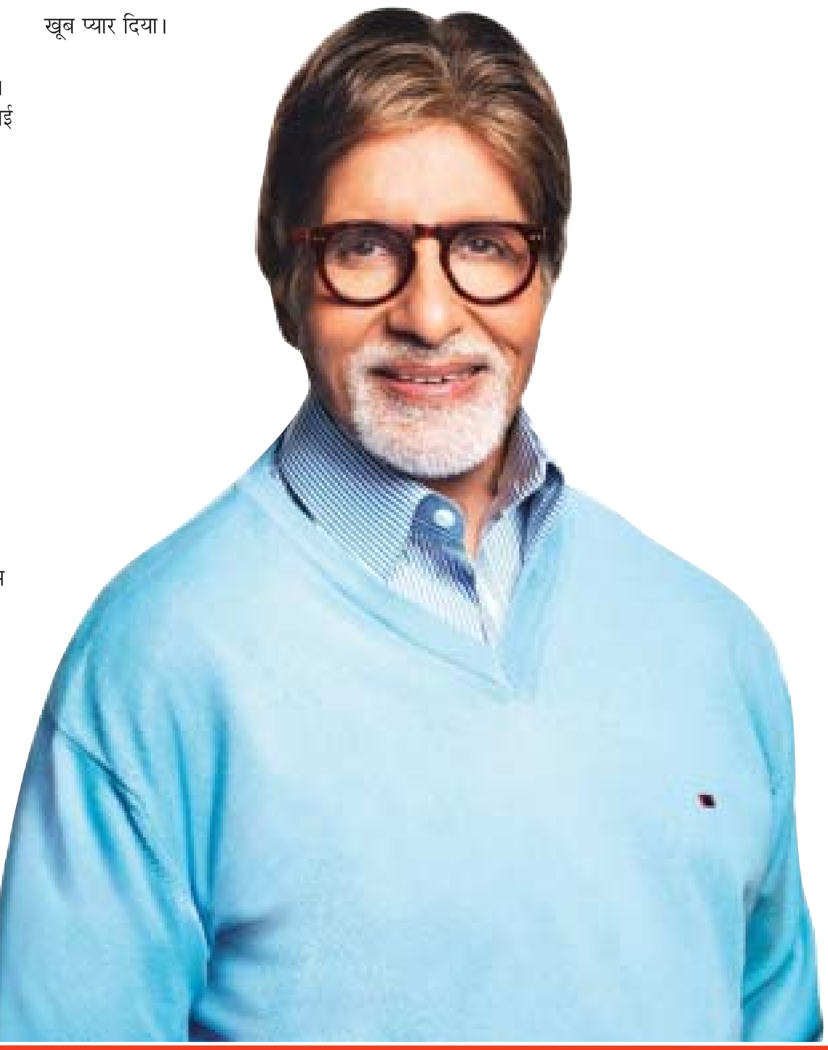

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित। शाखा कार्यालयः S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादकः प्रभात पांडेय सम्पर्कः 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com